14 गुना-विकास के पथ पर

आरसीवी : जश्न में भगदड़ 24

दिल्ली से प्रकाशित • जून, 2025 । वर्ष :14 । अंक :163 । मूल्य : 20

RNI No. DELHIN/2011/41355

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति, पीएसयू और अपराध पर केंद्रित पत्रिका

एक पेड़ माँ के नाम

PRIME INDIA MEDIA HOUSE → PRIME CRIME INDIA
www.primecrimeindia.com

PSU TODAY
News Channel for PSU & Corporate world

NETA INDIA
www.netaindia.com

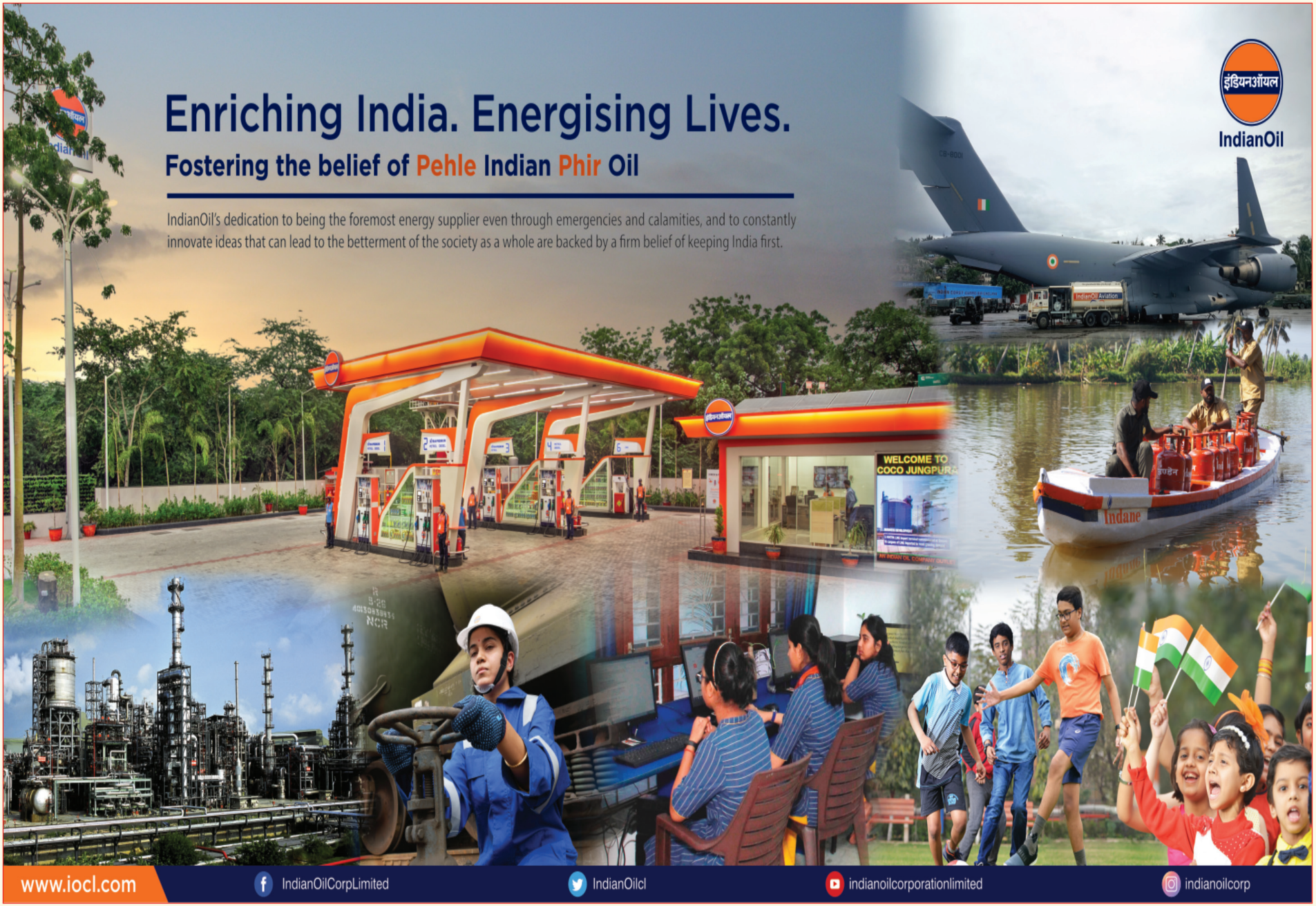
Enriching India. Energising Lives.
Fostering the belief of Pehle Indian Phir Oil
IndianOil's dedication to being the foremost energy supplier even through emergencies and calamities, and to constantly innovate ideas that can lead to the betterment of the society as a whole are backed by a firm belief of keeping India first.
इंडियनऑयल
IndianOil
WELCOME TO COCO JUNGPURA
Indane
www.iocl.com
IndianOilCorpLimited
IndianOilcl
indianoilcorporationlimited
indianoilcorp

संपादकीय

नासिर खान
संपादक

पाक समर्थित आतंकवाद

पाकिस्तानी सरकार, सेना और आतंकियों के गठजोड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और भारत के इस दावे की पुष्टि कर रही हैं कि आतंकवाद इस्लामाबाद की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। ताजा सबूत वह रैली है, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद खान ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों- सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद के साथ मंच साझा किया। इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को दुनिया बेहतर ढंग से समझ सकती है। सीमा पर टकराव के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की कथित जीत का जश्न मनाने के लिए वैश्विक स्तर पर घोषित आतंकी घूम-घूमकर रैलियां कर रहे हैं, वह इस्लामाबाद के इस झूठ की पोल खोल देता है कि पहलगाम के पीछे उसका हाथ नहीं। खुद को विजेता साबित करने के उतावलेपन में पाकिस्तान ने अपना नकाब हटा दिया है।

सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम का मुख्य साजिशकर्ता है और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में उसकी हैसियत डिप्टी चीफ की बताई जाती है। इसी तरह तलहा सईद लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है। भारत और अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा था, पर चीन ने बचा लिया।

आतंकी, भारत में अस्थिरता और आतंकवाद फैलाने की कोशिशों का समर्थन ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट में इनका हाथ था। शुरू से यह अंदेशा जताया जा रहा था कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें थीं और अब यह साबित हो रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि ढाका में कट्टरपंथियों को मजबूती मिलने से 1971 की उसकी हार का बदला पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। वहां की स्टेट पॉलिसी में आतंकियों के दखल और असर को देखते हुए वैश्विक बिरादरी को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। FATF की इस महीने होने वाली बैठक में भारत यह मुद्दा उठा सकता है ताकि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। ◆◆◆

इस अंक में

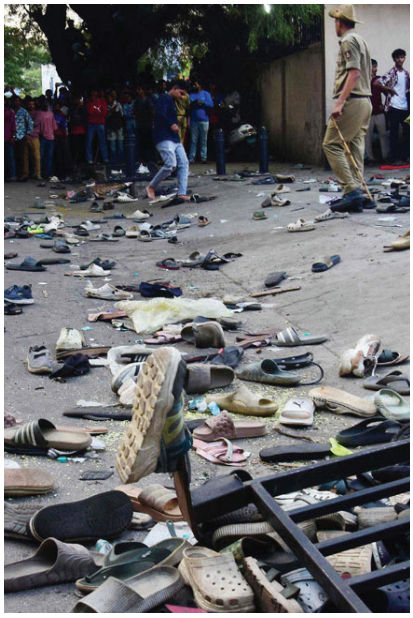

| 06 | एक पेड़ माँ के नाम

कवर स्टोरी

आईपीएल 2025

| 24 | जीत के बाद जश्न में भगदड़ मचने से 11 मौत

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

DAVP No.0813F27125-025 | वर्ष : 14 । अंक : 163 । जून, 2025 । मूल्य ₹20 | RNI No.DELHIN/2011/41355

संपादक
नासिर खान

सलाहकार संपादक
राकेश त्रिपाठी

राजनीतिक संपादक
ए. पी. सिंह

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रशांत दत्त मिश्रा

कानूनी सलाहकार
डी.बी.गोस्वामी, सलीम खान
(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव
समीर अख्तर

विदेश प्रतिनिधि

विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख
सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख
अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख
श्वेतांक वर्मा

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख
शाहिद अस्करी

सोनभद्र ब्यूरो प्रमुख
संजय सिंह

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख
योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख
शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख
राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख
साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख
रानू पाठक

मध्य प्रदेश

10 **विकास के पथ पर गुना जिला**

देश – विदेश

32 **आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का पैगाम**

सम्पादकीय.....03

विषय सूची.....04

एनजीटी ने बिना भूकंपीय अध्ययन के.....09

पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर.....17

ऑपरेशन सिंदूर.....18

मोदी ने किया चिनाब ब्रिज का उद्घाटन.....28

सीबीआई करेगी नेगी प्रकरण की जांच.....34

100 दिन नीतियां बनाने और काम 36

कोरोना की दस्तक.....39

राजस्थान की डिप्टी सीएम का हल्दीघाटी.....42

बच्चे पढ़ेंगे देश पर गर्व करने वाली 44

गढ़वाली सिनेमा की नयी उड़ान, द्वि होला.....46

काले धन पर फिर से 'रेड'.....48

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख
संजय सिन्हा

उत्तराखण्ड ब्यूरो प्रमुख
सत्यजीत पंवार

पश्चिम बंगाल ब्यूरो प्रमुख
नवीन राय

मथुरा ब्यूरो
विनय चौधरी (संवाददाता)

कानपुर ब्यूरो
अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)

इलाहाबाद ब्यूरो
गुफरान खान (वरिष्ठ संवाददाता)

मीरजापुर ब्यूरो

कला एवं सज्जा

रामदूत ग्राफिक्स

संजीव कुमार जैन (वरिष्ठ संवाददाता)

चंदौली ब्यूरो
उपेन्द्र राय (संवाददाता)

बलिया ब्यूरो
डॉ. कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता)

आरा ब्यूरो
विमलेष कुमार (संवाददाता)

हाजीपुर ब्यूरो
राहुल कुमार (संवाददाता)

दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी
नरेश कुमार श्रीवास्तव

कार्यालय

संपादकीय कार्यालय
आर-141/3 रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

कार्पोरेट ऑफिस
91 प्रथम मंजिल, जे एंड के ब्लॉक लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
संपर्क : +91 9718647540 एवं +91 11-46536014

ईमेल : primespectator@gmail.com
primeindiamediahouse@gmail.com
वेबसाइट : primecrimeindia.com & netaindia.com

❑❑❑

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा ANEJA PRINTERS C&11, SECTOR10, NOIDA (UP) से मुद्रित तथा आर-141/3 रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित।

कवर सहित 52 पेज

सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टेटर के किसी भी रचना के प्रकाशन से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखक के निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

एक पेड़
माँ के नाम

नासिर खान, वरिष्ठ पत्रकार

◆ हम अपनी धरती की रक्षा करने के लिए अपने प्रयासों को और सुदृढ़ बनाएं : नरेंद्र मोदी

◆ 'एक पेड़ मां के नाम' पहल को व्यापक बनाने का लिया संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने का आह्वान करते हुए पर्यावरण को हरित और बेहतर बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर कार्यरत लोगों के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। वहीं उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, आइए हम अपनी धरती की रक्षा करने और हमारे समक्ष आने वाली चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की दिशा में अपने प्रयासों को और सुदृढ़ बनाएं। हमारे पर्यावरण को हरा-भरा और बेहतर बनाने के लिए भी जमीनी स्तर पर कार्यरत सभी लोगों की मैं सराहना करता हूं।

प्रधानमंत्री ने लगाया भगवान महावीर वनस्थली उद्यान में एक पौधा

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली उद्यान में एक पौधा लगाकर 'एक पेड़ मां के नाम' पहल को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया। श्री मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखला में पुनः वनरोपण के महत्व का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अनेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है और इनके समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला और उसके बाहर, पारंपरिक पौधरोपण विधियों के अलावा, हम नई तकनीकों को प्रोत्साहित करेंगे, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां जगह की कमी है। श्री मोदी ने कहा कि पौधरोपण गतिविधियों को जियो-टैग किया जाएगा और मेरी लाइफ पोर्टल पर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने और पृथ्वी के हरित आवरण को बढ़ाने में योगदान देने का आग्रह भी किया। एक्स पर अपने पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा;ह्वआज, विश्व पर्यावरण दिवस पर, हमने एक विशेष वृक्षारोपण अभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल को मजबूत किया। मैंने दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली उद्यान में एक पौधा लगाया। यह अरावली पर्वतमाला को फिर से वनीकरण करने के हमारे प्रयास-अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का एक हिस्सा भी है। यह सर्वविदित है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में इस पर्वतमाला से संबंधित कई पर्यावरणीय चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिन्हें कम करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान इस पर्वतमाला से जुड़े क्षेत्रों का कायाकल्प करने पर है। हम संबंधित स्थानीय प्रशासनों के साथ मिलकर कार्य करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जल प्रणालियों में सुधार, धूल भरी आंधियों पर अंकुश लगाने, थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने आदि जैसी मुद्दों पर बल देने जा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला और उसके बाहर, पारंपरिक पौधरोपण विधियों के अलावा, हम नई तकनीकों को प्रोत्साहित करेंगे, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां जगह की कमी है। पौधरोपण गतिविधियों को जियो-टैग किया जाएगा और मेरी लाइफ पोर्टल पर उनकी निगरानी की जाएगी। मैं अपने देश के युवाओं से इस आंदोलन में भाग लेने और हमारी पृथ्वी के हरित आवरण में योगदान देने का आह्वान करता हूं। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीर्घकालीन विकास और हरित शहरी परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिल्ली सरकार की पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल हरित और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में योगदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली के नागरिकों के 'जीवन में सुगमता' में भी वृद्धि करेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा स्वच्छ और हरित दिल्ली का निर्माण! दीर्घकालीन विकास और हरित शहरी परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिल्ली सरकार की पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। यह दिल्ली के नागरिकों के 'जीवन में सुगमता' में भी वृद्धि करेगा।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली उद्यान में एक पौधा लगाकर 'एक पेड़ मां के नाम' पहल को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया।

प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। यह पौधा उन्हें गुजरात के कच्छ की उन वीरांगना माताओं और बहनों ने उपहार स्वरूप भेंट किया था, जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था। गुजरात की अपनी हाल की यात्रा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंदूर के पौधे का उपहार हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा।प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं-बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला है। यह पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी

विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। यह कई गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व करता है। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तभी से ही यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष, कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया है।

इतिहास

वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन (5-16 जून 1972) किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके दो साल बाद, 5 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। 1987 में इसके केन्द्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। इसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं।

महत्व

पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता हैं। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है।

एनजीटी ने बिना भूकंपीय अध्ययन के खनन पर लगाई रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संवेदनशील क्षेत्रों में बिना भूकंपीय अध्ययन के खनन पर रोक का निर्देश उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पापौन गांव में अवैध सोप स्टोन खनन के मामले की सुनवाई के दौरान दिया। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने बागेश्वर के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जब तक आवश्यक वैज्ञानिक मूल्यांकन और स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति न दी जाए। अदालत ने बागेश्वर के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जब तक आवश्यक वैज्ञानिक मूल्यांकन और स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति न दी जाए। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि पापौन गांव का इलाका भूगर्भीय दृष्टि से अत्यधिक नाजुक है। पत्थरों की संरचना कमजोर होने के कारण यहां अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में बिना वैज्ञानिक आकलन के खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना न केवल पर्यावरण बल्कि मानवीय जीवन और बुनियादी संरचनाओं के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अदालत ने निर्देश दिया कि भूकंपीय और पर्यावरणीय अध्ययन एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी), जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, और अन्य संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति को तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा

एनजीटी ने निर्देश दिया कि यूकेपीसीबी व बागेश्वर के जिलाधिकारी को 30 सितंबर 2025 तक ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति

सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि सोप स्टोन के अवैध खनन से पापौन गांव और आसपास के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। खनन से निकले मलबे ने पास की पुंगेर नदी को प्रदूषित कर दिया है, जिससे वहां के जलीय जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार यदि प्राकृतिक संसाधनों का यह दोहन यूं ही चलता रहा तो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल स्रोतों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे मानव और पशु जीवन दोनों संकट में आ सकते हैं।

एसजेवीएन ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया

एसजेवीएन ने शिमला स्थित कारपोरेट मुख्यालय तथा अपनी समस्त परियोजनाओं में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। इस अवसर पर अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक) ने सभी कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई तथा सतत एवं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अजय कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एसजेवीएन प्रकृति के पोषण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन में योगदान देना जारी रखना चाहिए क्योंकि यह एक स्थायी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस-2025 के उपलक्ष्य में कारपोरेट मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए क्विज प्रतियोगिता, ओरिगमी प्रतियोगिता और बेस्ट-आउट-ऑफ-प्लास्टिक वेस्ट प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक) ने इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर चंद्र शेखर यादव, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में, हरित जीवन-यापन के संदेश को बढ़ावा देते हुए गणमान्य व्यक्तियों को पौधे वितरित किए गए।विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम ह्लप्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, साथ ही वैश्विक नारा हम सभी मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, एसजेवीएन ने ई-अपशिष्ट संग्रहण अभियान चलाया, जिसमें सुरक्षित एवं उत्तरदायित्व से पूर्ण निपटान के लिए लगभग 30 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पदार्थों को सफलतापूर्वक एकत्रित किया। ◆◆◆

श्वेतांक वर्मा, मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

विकास के पथ पर मध्य प्रदेश का गुना जिला

विकसित भारत की तर्ज पर गुना बढ़ा रहा कदम : किशोर कन्याल

जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल के नेतृत्व में गुना जिला विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। अगर जिलाधिकारी की उपलब्धियों की बात करें तो जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल के नेतृत्व में गुना ने पहली बार सीएम हेल्पलाइन निराकरण में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में समूह 'अ' में गुना जिले ने प्रदेश स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विकसित भारत की तर्ज पर विकसित गुना अपने कदम लगातार बढ़ा रहा है। गुना को गुलाबों का शहर बनाए जाने हेतु पॉली हाउस में गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुंभराज क्षेत्र के धनिया को जीआई टैग पहचान मिले इस हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमआईएस गुना जिले में 182 पीएमआईएस वैकेंसी निकली थीं, जिसमें आवेदन हेतु 621 लक्ष्य रखा गया था, परंतु लक्ष्य के विरुद्ध 1432 आवेदन प्राप्त हुए तो लक्ष्य के 2।3 गुना था। पीएमआईएस अंतर्गत गुना जिला मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान पर है। ईट टू राइट- ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट फेज-4 के अंतर्गत जिला देश एवं प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचा।एक्सपोर्ट झगुना जिले से इनडायरेक्ट वे में धनिया एवं मसाला उत्पादों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है इसकी प्रकार पगारा स्थित औद्योगिक इकाई दीपक स्पीनर लिमिटेड द्वारा यार्न का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मंडी में आवक- कृषि उपज मंडी गुना में एक दिन में सर्वाधिक आवक 62191 कुंतल हुई जिसकी नीलामी उसी दिन कर दी गई।मोबाइल कोर्ट-जिले में राजस्व विभाग के प्रकरणों के निराकरण के लिए मोबाइल कोर्ट की शुरूआत की गई, जिसमें राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। रोजगार मेला-फरवरी माह में रोजगार एवं स्वरोजगार मेला में 70 बेरोजगारों को ऑफर लेटर वितरण एवं 140 स्वरोजगारियों को हित लाभ वितरण किया

गया। माह मार्च 2025 में रोजगार एवं स्वरोजगार मेला में 56 बेरोजगारों को ऑफर लेटर वितरण एवं 286 स्वरोजगारियों को हित लाभ वितरण किया गया।आयुष्मान-आयुष्मान कार्ड का मेगा कैंप दिनांक 22 मार्च 2025 को आयोजित किया गया जिसमें 6230 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसी प्रकार दिनांक 26 मार्च 2025 को आयोजित कैंप में 5835 आयुष्मान कार्ड बनाए गए।जनसुनवाई-जनसुनवाई में समस्याओं के निवारण के साथ साथ नेत्र, स्वास्थ्य चेकअप, आयुष्मान कार्ड एवं आधार कार्ड के कैंप लगाकर आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। वसूली-गुना जिले को 10 करोड़ का लक्ष्य राजस्व वसूली हेतु दिया गया था जो कि समय सीमा में पूर्ण कर लिया गया है। यह गुना जिले में पहली बार हुआ है।

गुना जिले के बारे में

गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में 5 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ था। 19वीं सदी के पूर्व गुना ईसागढ़ (अब जिला अशोकनगर में स्थित) जिले का एक छोटा सा गांव था। ईसागढ, जो कि 250-700 एवं 700-550 पूर्व में स्थित है, प्रभु यीशू के सम्मान में इसका नाम ईसागढ़ रखा। सन् 1844 में गुना में ग्वालियर की फौज रहती थी, जिसके विद्रोह करने के कारण सन् 1850 में इसे अंग्रेजी फौज की छावनी में तब्दील किया गया। सन् 1922 में छावनी को गुना से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया एवं नवंबर 5, 1922 को जिला मुख्यालय बजरंगढ़ से गुना स्थानांतरित कर दिया गया। सन् 1937 में जिले का नाम ईसागढ़ के स्थान पर गुना को रखा गया तथा ईसागढ़ एवं बजरंगढ़ को तहसील बनाया गया जिन्हे बाद में क्रमशः अशोकनगर गुना तहसील के रूप में परिवर्तित किया गया। सन् 1948 में राघौगढ़ को तहसील के रूप में शामिल किया गया। सन् 2003 में अशोकनगर को गुना से पृथक कर एक अलग जिला बना दिया गया। गुना ग्वालियर संभाग में स्थित है। जिले में गुना, आरोन, राघौगढ़,

मधुसूदनगढ़ , बमोरी, चाचोड़ा एवं कुंभराज सात तहसीलें तथा गुना, आरोन, राघौगढ़, चाचोड़ा , बमोरी पांच विकासखण्ड है। जिले में आबाद ग्रामों की संख्या 1264 तथा कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 425 है। साथ ही जिले में 5 जनपद पंचायतें तथा 2 नगरपालिका एवं 3 नगर पंचायतें हैं गुना में विधानसभा सीटो की कुल संख्या 4 है।

ऐसे पड़ा नाम

पहले ' डेविल्स किचन ' के नाम से मशहूर इस जगह का नाम 'गुना' तब पड़ा जब 1992 में तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गुना' की शूटिंग यहीं हुई थी। मोइर पॉइंट रोड पर स्थित ये गुफाएँ कोडईकनाल से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देवदार के जंगलों से होते हुए आप गुफाओं तक पहुँच सकते हैं।

जिलाधिकारी के बारे में

दिल्ली के गौतमपुरी की गलियों,पार्कों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने से लेकर मध्य प्रदेश के गुना का जिलाधिकारी बनने का सफर किशोर कन्याल का बेहद दिलचस्प है। बचपन से स्पोर्ट्समैन बनने का सपना लिए अपनी जिंदगी में कई उपलब्धियां हासिल करने वाले किशोर कहते हैं कि स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। उन्हें ब्यूरोक्रेट से ज्यादा स्पोर्ट्समैन बनने का शौक था क्योंकि ब्यूरोक्रेट का दायरा सीमित होता है लेकिन स्पोर्ट्समैन के दायरा की कोई सीमा नहीं होती है।

दिल्ली के गौतमपुरी स्थित एक सरकारी स्कूल से प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक की। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में हो गया जहां उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरनेशनल लॉ में डिप्लोमा किया और फिर एलएलबी की पढ़ाई पूरी की तो बहुत ही कम उम्र 21 वर्ष में मध्य प्रदेश में पीसीएस एलाइड बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने आगे बढ़ने की चाह नहीं छोड़ी और वह एक के बाद एक तीन बार मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा देकर अंततः पीसीएस प्रॉपर में जगह बनाई तो तरक्की की एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए। आज वह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वह समाज के लिए आए दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

फुटबॉल और क्रिकेट के दीवाने किशोर कन्याल को बचपन से ही खिलाड़ी बनने का शौक था। किशोरावस्था तक किशोर कन्याल खेल के दीवाने थे, क्रिकेट में बॉलिंग और कीपिंग करना बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह फुटबॉल में अच्छे फुटबॉलर की तरह खेलते थे। फुटबॉल में फारवर्ड प्लेयर के तौर पर खेला करते थे तो वही अच्छे हेडर भी थे। इन्हें थोड़ा सा मौका मिलता था तो गोल करने में नहीं चूकते थे। इसी तरह पढ़ाई में भी मेहनत की बदौलत अपने लक्ष्य को हासिल करने में नहीं चूकते थे जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में मध्य प्रदेश पीसीएस में इनका चयन हो गया।

मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस वर्ष 1998 बैच के पीसीएस अफसर किशोर कन्याल को उनके बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2013 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का कैडर दिया तो कन्याल ने अपने समाज के प्रति समर्पण को और बढ़ा दिया। रोजाना सुबह 6:30 बजे से दिनचर्या शुरू करने वाले कन्याल को रात करीब 12:00 बजे फुर्सत मिलती है तो कुछ घंटों की नींद पूरी कर लेते हैं। अपने रूटीन को बताते हुए वह कहते हैं कि हर मौसम में रोजाना सुबह 6:30 बजे तक वह मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं और फिर योगा वगैरह करने के बाद क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह 10:00 बजे तक दफ्तर पहुंचना और फिर दफ्तर में जनता की समस्याओं का निराकरण करते-करते उन्हें 12:00 बज जाते हैं और फिर दफ्तर का कुछ काम निपटाते हैं। इस तरह काम के दौरान लंच भी हो जाता है और फिर 3:00 बजे दफ्तर का काम निपटाने और मीटिंग वगैरह करने में शाम हो जाती है। शाम को घर पर भी दफ्तर चलता है। उनकी कोशिश होती है कि जीरो पेंडेंसी वर्क हो। इस तरह अक्सर रात के 12:00 बज जाते हैं और थककर सो जाते हैं।

इनके कामों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें पांच अप्रैल 2023 को शाजापुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया। शाजापुर में रहते हुए इन्होंने अपना काम बाखूबी निभाया। शाजापुर से सरकार ने कुछ दिनों के लिए इनका तबादला फॉरेस्ट विभाग में कर दिया। चूंकि किशोर कन्याल आम जनता से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट हैं इसलिए सरकार ने कुछ दिनों में इन्हें श्योपुर का जिलाधिकारी बनाकर भेजा। जिस वक्त इन्हें श्योपुर की कमान दी गई उस वक्त विधानसभा चुनाव होना था। जो कि श्योपुर जिले के लिए चुनौती भरा काम था। श्री कन्याल ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए विधानसभा चुनाव सुचारू ढंग से कराया तो चारो तरफ इनके प्रशासनिक कौशल्य की चर्चा होने लगी। ईमानदार व स्वच्छ छवि के अफसर होने का एक बार फिर राज्य सरकार ने इनको ईनाम के तौर पर गुना का जिलाधिकारी बनाया।

वह कहते हैं कि शहर को शानदार बनाने के लिए स्कूली बच्चे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि समाज में बच्चों के जरिए प्रभावशाली ढंग से सकारात्मक संदेश आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कन्याल के खुशहाल परिवार में माता,पत्नी बेटी और बेटा है। माता ग्रहणी और पिता दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग (डेसू) में ऑफिस सुपरीटेंडेंट थे।पत्नी ने ग्रेजुएशन और एमबीए कर रखा है। जबकि बेटी देवांशी ने बी टेक और एडवरटाइजिंग में मास्टर्स किया है। देवांशी भरतनाट्यम कला की अच्छी डांसर भी है। कई बड़े स्टेज शो में पार्टिसिपेट करने के अलावा भारतनाट्यम

डांस में काफी पारंगत हो चुकी है। फिलहाल एक खुशहाल परिवार के साथ किशोर कन्याल अपने दायित्वों के प्रति अग्रसर है।

शासन की योजनाओं से जुड़कर महिलाएं बढ़ रही है समृद्धि की ओर

दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2025 को भोपाल के गुलाब उद्यान में 44वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में संपूर्ण भारत से गुलाब के लगभग 700 उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत किए गए। गुना जिले की उन्नतशील कृषक श्रीमती लता अग्रवाल निवासी ग्राम मावन एवं इंदु जादौन निवासी हनुमान टेकरी के पास गुना ने अपने पॉलीहाउस में उगाए गए गुलाब के डच रोज कट फ्लावर प्रदर्शनी में भेजकर जिले का गौरव बढ़ाया। लता अग्रवाल को व्यावसायिक पुष्प उत्पादकों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा इंदु जादौन को उसी श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।गुना जिले में इन दोनों पॉलीहाउस का निर्माण एवं गुलाब उत्पादन कार्य उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के अंतर्गत किया गया है। विभाग द्वारा पॉलीहाउस निर्माण और गुलाब की खेती पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है। गुना जिले में गुलाब की खेती लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में पॉलीहाउस के माध्यम से गुलाब की खेती की जा रही है। यहां उत्पादित गुलाब दिल्ली, जयपुर, भोपाल, झांसी जैसे बड़े शहरों में विक्रय के लिये भेजे जाते हैं। एक एकड़ में गुलाब की खेती से किसान प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। वर्तमान में एक गुलाब कट फ्लावर का बाजार मूल्य लगभग 15 रुपए है। गुना जिले की श्रीमती लता अग्रवाल और सुश्री इंदु जादौन ने गुलाब की खेती में नई ऊंचाइयों को छूकर यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करके कृषि में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की जा सकती है।

खनिज माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही सतत जारी

जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल के निदेर्शानुसार जिले के खनिज क्षेत्रों पर खनन, परिवहन की अवैध गतिविधि करने वालों के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग प्रभारी श्रीमति जिया फातिमा के निर्देशन में खनिज टीम द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2025 को खनिज अवैध उत्खनन/ परिवहन/ अवैध भंडारण की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच/ निरीक्षण के दौरान एक डंपर क्रमांक MP08GA1888 को चांचौड़ा एबी रोड पर खनिज गिट्टी का ओवर लोड परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर थाना बीनागंज की अभिरक्षा में रखा गया है। एवं तहसील चांचौड़ा के ग्राम भैसुआ में स्वीकृत खदान की रॉयल्टी वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीमांकन तथा गड्ढे की माप करने की कार्यवाही की गई तथा जब्तशुदा वाहन का प्रकरण खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर को पेश किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सतत कार्यवाही जारी खनिज शाखा प्रभारी श्रीमती जिया फातिमा के मार्गदर्शन में खनिज दल द्वारा दिनांक 07 अप्रैल को भी खनिज अवैध उत्खनन/ परिवहन/ अवैध भंडारण की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच के दौरान ग्राम रूठियाई में एक जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी का अवैध कर परिवहन करते समय 5 ट्रैक्टर ट्राली एवं ग्राम कबूलपुरा में रेत का अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर एक जेसीबी जब्त कर थाना रूठियाई की अभिरक्षा में रखे गये है।

सेना के जवानों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 07 अप्रैल 2025 से रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सेना के जवानों के लिए तीन माह का आवासीय स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिसका जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल एवं पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा की मुख्य उपस्थिति में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे,अनुविभागीय अधिकारी गुना शिवानी पाण्डे सहित मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एफडीडीआई गुना की कार्यकारी निदेशिका मंजु मनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए एफडीडीआई गुना की कार्यकारी निदेशिका श्रीमती मंजु मनकी ने बताया कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था,आज देश में डिजाइन शिक्षा के क्षेत्र में एकराष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है। एफडीडीआई की उपस्थिति देशभर में फैली हुई है जिनमें नोएडा (मुख्यालय), गुना, फुरसतगंज, रोहतक,

चंडीगढ़, जोधपुर, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, अंकलेश्वर, चेन्नई और छिंदवाड़ा जैसे 12 स्थानों पर इसके अत्याधुनिक परिसर संचालित हैं, जिनमें से 7 7 Centre of Excellence हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एफडीडीआई में विभिन्न विषयों में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें फुटवियर डिजाइन और प्रोडक्शन,फैशन डिजाइन,लेदर गुड्स एवं एसेसरीज डिजाइन,रिटेल एवं फैशन मर्चेंडाइजिंग प्रमुख हैं।

नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा

दिनांक 03 अप्रैल 2025 को स्टार्टअप महाकुंभ,भारत मंडपम,नई दिल्ली में एफडीडीआई द्वाराई-सेल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों के इनोवेटिव विचारों को मूर्त रूप देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है। एफडीडीआई का फोकस सस्टेनेबल फैशन और जिम्मेदार डिजाइन पर भी है।

हनुमान जयंती पर भव्य तरीके से आयोजित होगा टेकरी मेला

श्रद्धा, आस्था और उल्लास का पर्व एक बार फिर पूरे भव्य स्वरूप में मनाया गया। श्री हनुमान टेकरी धाम में इस वर्ष भी 12 अप्रैल, शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। परंपरागत और ऐतिहासिक इस आयोजन की तैयारियां एक माह पहले से ही शुरू कर दी थी और ट्रस्ट के साथ-साथ जिला प्रशासन ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। पूरे मंदिर परिसर को दुर्लभ और नायाब फूलों से सजाया गया था। गर्भगृह में आर्केड, रजनीगंधा, जरबेरा, गुलाब, मोगरा और कई विदेशी फूलों से श्री बालाजी का दिव्य श्रृंगार किया गया था। वहीं, पिछले 10 दिनों से जारी आकर्षक विद्युत साज-सज्जा श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए गए। मेले में आधुनिक झूले, चाट-चौपाटी, व मनोरंजन के विविध साधन आकर्षण का विशेष केंद्र होंगे। यह मेला सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक रंगों से भी सराबोर रहा। जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की। ट्रस्ट के साथ-साथ बागेश्वर धाम की टीम के 300 से अधिक सेवाभावी स्वयंसेवक और पुलिस बल मेला व्यवस्था में तैनात रहे। सभी विभागों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई।

श्री हनुमान टेकरी ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी थी कि श्रद्धालुओं के लिए रात्रि 12:15 बजे से पट खोल दिए गए थे। मंगला आरती सुबह 4:15 बजे और शयन आरती रात 11:45 बजे संपन्न हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। हनुमान जयंती पर इस बार टेकरी मेला और भी भव्य तरीके से आयोजित कराने के लिए जिलाधिकारी किशोर कन्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में लगातार महत्वपूर्ण बैठक थीं। बैठक में पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे सहित मंदिर समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 'पोषण भी पढ़ाई भी' का प्रशिक्षण

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के निदेर्शानुसार एवं जिलाधिकारी गुना किशोर कुमार कन्याल के मार्गदर्शन में गुना जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकताओं को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 24 से 26 मार्च 2025 एवं द्वितीय बैच का प्रशिक्षण दिनांक 27 से 29 मार्च 2025 तक प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का संचालनालय मबावि भोपाल से नियुक्त अधिकारी सीमा रघुवंशी उप संचालक महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा भी भ्रमण कर निरीक्षण किया गया।इसी क्रम में संभागीय अधिकारी सीमा शर्मा संयुक्त संचालक मबावि ग्वालियर द्वारा गुना जिला अंतर्गत परियोजना गुना ग्रामीण की आंगनबाड़ी कार्यकताओं के पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संयुक्त संचालक सीमा शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकताओं को पोषण भी पढ़ाई भी के महत्व के बारे में बताया। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उददेश्य आंगनबाड़ी कार्यकताओं में ईसीसीई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना तथा आंगनवाड़ी कार्यकताओं को बच्चों के विकास के आयामों के मूल्यांकन में क्षमता वृद्धि कर सक्षम बनाना है।पोषण भी पढ़ाई भी का प्रशिक्षण संबंधित परियोजना की मास्टर ट्रेनर एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान दिनेश कुमार चंदेल जिला कार्यक्रम अधिकारी मबावि गुना समय समय पर अलग-अलग दिनांकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त प्रशिक्षणों का आज दिनांक 29.03.2025 को सफलतापूर्वक समापन किया गया।

गुना के गुलाब पूरी दुनिया को कर रहे हैं आकर्षित

जिले में पॉलीहाउस तकनीक से उगाए जा रहे गुलाब न केवल अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि किसानों के लिए आय का एक नया और स्थायी स्त्रोत भी बन रहे हैं। ह्लताजमहलह्व किस्म के गुलाब अपनी आकर्षक रंगत और मनमोहक खुशबू के कारण बाजार में खास पहचान बना रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक श्री केपीएस किरार ने बताया कि कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में ह्लहर घर गुलाबह्व अभियान को साकार करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत किसानों को पॉलीहाउस में गुलाब उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता, अनुदान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह तकनीक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और उच्च गुणवत्ता वाले फूलों का उत्पादन सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो रही है।उद्यानिकी विभाग पॉलीहाउस के साथ-साथ खुले खेतों में भी गुलाब उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। विभाग की ओर से गुलाब की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं, जिससे जिले में फूल उत्पादन को नई ऊँचाइयाँ मिल रही हैं। गुलाब की महक से महकेगा भविष्यगुलाब की बढ़ती माँग को देखते हुए जिले के किसान अब व्यावसायिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों में गुना के गुलाबों की माँग बढ़ने से किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। सरकार की पहल और किसानों की मेहनत से यह क्षेत्र आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिखने की ओर अग्रसर है। इससे न केवल स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि गुना जिले की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।

आयुष्मान कार्ड और फार्मर रजिस्ट्री अभियान पर नजर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जिला पंचायत) अभिषेक दुबे द्वारा आयुष्मान कार्ड एवं फार्मर रजिस्ट्री महाभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत हिलगना में कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुष्मान कार्ड के लंबित हितग्राहियों की सूची की जानकारी ली गई एवं शेष बचे कार्ड को अभियान के दौरान पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने ग्राम पंचायत

में पेयजल हेतु नलजल योजना के संचालन को देखा एवं पेयजल संकट से बचने हेतु एवं करारोपण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत दुबे ने ग्राम पंचायत भवन को अच्छे से संधारित करने के लिए ग्राम पंचायत की सराहना की। वहीं ग्राम पंचायत भवन के अतिरिक्त किचेन शेड नवीनीकरण के कार्य एवं स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान एसडीएम शिवानी पांडे, सीईओ जनपद गुना गौरव खरे, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक मुरारी एवं अन्य विभागीय अमला उपस्थित रहा। जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने के निर्देश जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को दिये गये हैं। इसी क्रम में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा फार्मर रजिस्ट्री बनाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज तहसील मकसूदनगढ़ के ग्राम बारोद में तहसीलदार धीरेंद्र गुप्ता ने राजस्व वसूली एवं फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण गया। तहसील चांचौड़ा अंतर्गत ग्राम पैंची में नायब तहसीलदार शुभम जैन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया। तहसील बमोरी अंतर्गत ग्राम पांचोरा में तहसीलदार देवदत्त गोलिया द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। ऐसे किसान जिन्हें पीएम एवं सीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उनके लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य किया गया है, ऐसी स्थिति में आगामी समय में उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना आवश्यक होगा।

एक पेड़ माँ के नाम की हुई शुरूआत

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुना जिले में आज एक प्रेरणादायक पहल की गई। सिंगवासा तालाब परिसर में वृहद पौधरोपण कर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों से लेकर आमजन तक ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।इस अवसर पर विधायक पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविन्द धाकड़, नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, उपाध्यक्ष धरम सोनीसहितकलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, एसडीएम शिवानी पांडे, तहसीलदार जीएस बैरवा, उपसंचालक उद्यानिकी केपीएस किरार, परियोजना अधिकारी तेज सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। विधायक श्री शाक्य ने कहा कि ह्लआज गंगा दशहरा का पावन दिन है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम सबको संकल्प लेना चाहिए। पेड़-पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। नगर पालिका अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि पौधरोपण के साथ-साथ हमें इन पौधों की देखरेख कर उन्हें बड़ा करना है, तभी यह अभियान सार्थक होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सिकरवार ने अपील की कि ह्लआगामी मानसून को देखते हुए प्रत्येक नागरिक पौधरोपण करें और इसे एक सामाजिक

जिम्मेदारी मानें। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री धाकड़ ने कहा कि ह्लपेड़ हमें न केवल शुद्ध वायु देते हैं, बल्कि छाया, फल और बेहतर वातावरण भी प्रदान करते हैं। अधिक से अधिक पौधे लगाकर हम भावी पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण दे सकते हैं।ह्व आज इस अवसर पर सिंगवासा तालाब के पास बड़ी संख्या में पौधे रोपे गए और सभी ने यह संकल्प लिया कि वे कम से कम एक पौधे की देखभाल अवश्य करेंगे।

जमाखोरी-कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही

कलेक्टर किशोर कन्याल के निदेर्शानुसार जिले में जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत पारित दो आदेश अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चावल को दिनांक 31 जनवरी 2025 को सुनील साहू पुत्र बनवारीलाल साहू निवासी लवकुश नगर बंगला मोहल्ला गुना एवं हेमराज अहिरवार निवासी पिपरौदा खुर्द द्वारा पिकअप वैन वाहन क्रमांक टढ 08 ऋ0898 में अवैध रूप से 22 चावल जप्त किया गया था। वाहन में उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चावल के संबंध में कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त चावल मय वाहन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने के कारण जप्त किया जाकर ईसी एक्ट की धारा 3/7 के तहत प्रकरण कायम किया गया। मंगल साहू पुत्र बारेलाल साहू निवासी पनबाडीहाट चौराह बायपास आरोन का निरीक्षण खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा करने पर 40 क्विंटल चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना पाया गया। चावल के संबंध में मंगल साहू द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रस्ताव में नोटिस जारी कर सुनवाई की गई। सुनवाई उपरांत अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विचार उपरांत अनावेदकों के पास जप्त चावल अवैध परिवहन किये जाने का कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण जप्त 62 क्विंटल चावल को राजसात किया गया एवं वाहन पिकअप वैन क्रमांक टढ 08 ऋ0898 को उक्त कृत्य में संलिप्त पाये जाने से शासन हित में राजसात किया गया है। आदेश में जिला आपूर्ति अधिकारी जिला गुना को निर्देशित किया गया है कि, राजसात किये गये चावल की नीलामी बाजार भाव पर कराई जाकर राशि शासन मद में जमा कराई जाए। तथा जप्त पिकअप वाहन क्रमांक टढ 08 ऋ0898 की राशि राजसात करने व राशि शासन मद में जमा कराये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन

एफडीडीआई (फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट), गुना परिसर में आज ह्लप्रतिभा सम्मान समारोह 2025ह्व का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं के 300 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने सत्र 2024झ्र25 में 60प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किए।मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी श्री किशोर कुमार कन्याल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम श्रीमती शिवानी पांडे और तहसीलदार श्री जीएस बैरवा उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा में निरंतर प्रयास और समर्पण की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एफडीडीआई गुना की कार्यकारी निदेशक श्रीमती मंजू 'मन' द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इसके पश्चात विद्यार्थियों को प्रशंसा-पत्र व स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लेकर बच्चों की सफलता का उत्सव मनाया।इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले लव कौशिक को विशेष रूप से मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले अन्यशीर्ष 10 रैंक धारक विद्यार्थियों को भी बेस्ट अचीवर्स अवॉर्ड ह्लप्रदान किया गया, जिससे पूरे सभागार में उत्साह और गौरव का माहौल रहा।कार्यक्रम का संचालन और समग्र समन्वय श्री मनोज कुमार शर्मा (अट, एफडीडीआई गुना) द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक मंजू 'मन' ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि झ ह्लएफडीडीआई का उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें 12वीं के बाद एक सशक्त और भविष्योन्मुखी करियर के लिए तैयार करता है। यहाँ से पढ़े छात्र देश-विदेश की नामचीन कंपनियों में सफलतापूर्वक नियुक्त हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एफडीडीआई द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों और रोजगार अवसरों की विस्तृत जानकारी दी, और छात्रों को इस संस्थान से जुड़ने के लाभ समझाए।इस अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में परिसर में सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनसमुदाय को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने हेतु प्रेरित किया।कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल,एसडीएम शिवानी पांडे और तहसीलदार जीएस बैरवा ने भी विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि वे एफडीडीआई जैसे संस्थानों से लाभ उठाएं, जो उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार आधुनिक, व्यावसायिक और करियर उन्मुख शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एफडीडीआई गुना, भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। ◆◆◆

श्वेतांक वर्मा, मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

घर वापसी अभियान के तहत 47 मजदूरों को मुक्त कराकर घर पहुंचाया

मध्य प्रदेश के गुना जिले के जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर चांचौड़ा क्षेत्र में 47 मानसिक रूप से अस्वस्थ और असहाय मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। इन सभी मजदूरों को बंधक बनाकर खेतों, होटलों और ढाबों में काम कराया जा रहा था। जिला प्रशासन मिल शिकायतों पर ह्घर वापसी अभियानह्व के तहत जब गंभीरता से इस मामले की जांच की गई, तो हकीकत बेहद दर्दनाक निकली। सोमवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 47 मानसिक विक्षिप्त मजदूरों को दबंगों के कब्जे से छुड़ाया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। चांचौड़ा उपखंड क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर एसडीएम रवि मालवीय ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने राजस्व विभाग, पुलिस, और नगरपालिका के अधिकारियों की संयुक्त पांच टीमें गठित कीं। शुक्रवार सुबह इन टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर जाकर दबिश दी। जिन जगहों पर मजदूरों के बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना मिली थी, वहां खेतों, ढाबों और होटलों की गहन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कई मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग खेतों में काम करते हुए पाए गए, जबकि कुछ ढाबों पर बर्तन धोते या सफाई करते मिले। इनसे काम तो लिया जा रहा था, लेकिन बदले में सिर्फ खाना दिया जाता था। घंटों लगातार मजदूरी कराई जाती थी। पहली ही कार्रवाई में प्रशासन ने 16 लोगों को रेस्क्यू किया। सोमवार को प्रशासन ने चांचौड़ा क्षेत्र में ह्घर वापसी अभियानह्व के तहत एक बड़ा शिविर लगाया। बीनागंज पुलिस चौकी परिसर में लगाए गए इस शिविर में कुल 47 असहाय और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को लाया गया। इनमें से कई लोगों को गुप्त रूप से अज्ञात लोगों द्वारा चौकी के बाहर छोड़ दिया गया था, जबकि कुछ को सड़क किनारे लावारिस हालत में छोड़ा गया था। आम नागरिकों की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अमले ने उन्हें शिविर तक पहुंचाया। शिविर में पहुंचे सभी लोगों का सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें शिवपुरी स्थित ह्अपना घर आश्रमह्व भेजने की व्यवस्था की, जहां उनके समुचित पुनर्वास की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है, ताकि उनकी निगरानी की जा सके और भविष्य में उन्हें फिर से किसी शोषण का शिकार न होना पड़े। शिवपुरी भेजे जा रहे इन लोगों से खुद कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बायपास पर मुलाकात की। उन्होंने सभी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन व्यक्तियों को आश्रम में समुचित देखभाल, उपचार और पुनर्वास मिले। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

◆ डीएम किशोर कन्याल और एसडीएम रवि मालवीय का प्रयास काबिले तारीफ

डीएम की अपील

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी असहाय, मानसिक रूप से बीमार या मजबूर लोगों से अवैध रूप से काम करवाया जा रहा हो, तो उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन या पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी एक गंभीर अपराध है। ◆◆◆

पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर

असम और इससे सटे उत्तर पूर्वी राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके.बाढ़ की चपेट में आ गए है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते 48 घंटों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई इलाकों में पानी भरने की खबरें मिल रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 31 मई की शाम को जारी की गई एक रिपोर्ट में बाढ़ से असम के 12 जिलों में 175 गांव डूबने की जानकारी दी गई है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि कई और इलाके.बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसकी रिपोर्ट रविवार शाम तक विभाग को मिल पाएगी। बाढ़ और भूस्खलन की अलग-अलग हुई घटना में अब तक असम में आठ लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 60 हजार से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम के अलग-अलग इलाकों में सैकड़ों की संख्या में लोग अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने आए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान लखीमपुर ज़िले में हुआ है। जिला प्रशासन ने लखीमपुर में दस से अधिक राहत शिविर खोले हैं। राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए प्रशासन ने दाल, चावल, सरसों का तेल, नमक, चिवड़ा और गुड़ उपलब्ध करवाया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि शनिवार को बाढ़ के पानी में डूबने से लखीमपुर में एक और गोलाघाट में दो लोगों की मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले गुवाहाटी को बोंडा में भूस्खलन के कारण पांच लोगों की मौत हुई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है और बाढ़ से निपटने के लिए हरसंभव सहायता की पेशकश की है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार एक्स पर पोस्ट किया, ह्यमाननीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ देर पहले मुझे फोन किया और मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया है कि उन्होंने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के गवर्नर से बात की है और ताजा स्थिति की जानकारी ली है, साथ ही स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह की मदद का वादा भी किया है।रविवार शाम हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया पर असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि सिलचर, करीमगंज और कई और जगहों पर भारी बारिश हो रही है। वहीं किबितू, हाउलियांग और कलाकतांग समेत अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है जिस कारण निचली नदियों में पानी का स्तर बढ़ सकता है।उन्होंने लिखा कि नदी के किनारे निचली जगहों पर रहने वाले लोग सतर्क रहें और स्थानीय दिशानिदेशों का पालन करें। असम के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। असम के अलावा सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं, जहां बाढ़ के कारण सड़कें बह गईं, घर तबाह हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह अभी जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में हैं। पूरा देश भी यही चाहता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर अभी अर्ध विराम लगा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, 'आतंकी हमले की कोई नई घटना होते ही, और मजबूत जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर पुनः ऑन होगा।

कहने को पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन वहां 'लोक' का 'शासन' सिर्फ मुखौटा है। असल सत्ता सेना के पास है। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास सेना नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना के पास वह देश है। हार के बावजूद वह भारत के साथ बार-बार छद्म युद्ध छेड़ता है, यह उसका प्रमाण है। क्योंकि, कोई 'लोक-शासन' बार-बार युद्ध या सैन्य संघर्ष नहीं करेगा। पांच युद्ध हारने के बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में प्रशिक्षित आतंकवादी भेज दिए, जिन्होंने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। वह भी महिलाओं के सामने, उनके पतियों से धर्म पूछकर। ऐसी निर्मम हत्याएं कभी नहीं हुईं। पाकिस्तानी सेना ने भारत को छठे युद्ध के लिए जानबूझ कर उकसाया। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित हो गया। लेकिन, 2014 से देश में एक ऐसी सरकार है, जो आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देती है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के आका, दोनों ही 2016 और 2019 में क्रमशः सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक के रूप में नए भारत की कार्रवाई देख चुके हैं। बावजूद इसके, उन्होंने भारत को फिर उकसाया। इसलिए इस बार भी भारत ने

जवाबी कार्रवाई करने में देरी नहीं लगाई। भारतीय कार्रवाई हुई। पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और विस्तृत आकार में।

पहलगाम आतंकी हमले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा बीच में स्थगित कर दी। स्वदेश लौटने पर पहले उच्चस्तरीय बैठक एयरपोर्ट पर ही ली। उसके बाद लगभग हर दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुखों, कैबिनेट कमिटी ऑन सेक्यूरिटी (सीसीएस) के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी। एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुखों से स्पष्ट कहा, 'आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका सेना खुद तय करे। सरकार उनके साथ अडिगता से खड़ी है। एक उच्चस्तरीय बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया। आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई 7 मई को हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के नौ ठिकानों को चिन्हित किया। और, 'ऑपरेशन सिंदूर' ऑन हुआ। सात मई को रात एक बजकर पांच मिनट पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के फाइटर ने एयरबेस से उड़ान भरी और 25 मिनट में अपने टारगेट (9 आतंकी ठिकानों) को नेस्तनाबूद करके वह सुरक्षित एयरबेस वापस पहुंच गया। इस बार सेना के टारगेट में बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और मुरीदके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय भी थे। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में हैं। यह पहली बार था, जब भारत ने 1971 के बाद पाकिस्तान के दिल पर हमला किया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को एक सटीक रणनीति के तहत सफल बनाया। इसमें किसी भी सैन्य या नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया गया। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय सहित सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। भारतीय सेना का हमला इतना सटीक था कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए। इसके अलावा उसके दो बेहद करीबी आतंकी भी इसमें मारे गए। इस कार्रवाई के जरिये भारत ने पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को एक बार फिर स्पष्ट संदेश दे दिया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दो महिला सैन्य अधिकारियों ने देश-दुनिया को जानकारी दी। भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी, ले. कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया। ले. कर्नल सोफिया ने कहा, 'पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। नौ आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, जो पाकिस्तान और पीओके, दोनों में फैले हुए थे। हमारा पहला लक्ष्य पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थित सवाई नाला कैंप था। यह लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र था। पिछले साल सोनमर्ग, गुलमर्ग और अब पहलगाम में हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों ने यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया था।' वहीं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सात मई को रात एक बजकर पांच मिनट से एक बजकर 30 मिनट के बीच अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए किया गया। इस ऑपरेशन में किसी भी नागरिक बुनियादी ढांचे और नागरिकों की जान को नुकसान नहीं हुआ है।

अपुष्ट आंकड़े बताते हैं कि भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत और भारतीय सेनाओं ने नौ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर अपने अभियान को पूरा मान लिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया। 7-8 मई को पाकिस्तान ने कश्मीर के अवंतीपोरा से लेकर गुजरात के कच्छ के भुज तक, उत्तर से पश्चिमी सीमा तक, भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों, धार्मिक एवं नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। एक साथ समूह में ड्रोन्स और मिसाइलों से इन ठिकानों पर हमले किए। जम्मू,

उधमपुर एवं पठानकोट सैन्य स्टेशनों पर मिसाइलों और समूह ड्रोन हमलों के अलावा नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी भी की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। अब बारी भारतीय ड्रोन्स और मिसाइलों द्वारा जवाबी कार्रवाई की थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ जवाबी कार्रवाई की।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। भारत के हमलों से पाकिस्तान के छह एयरबेस के रनवे और भवन ध्वस्त हो गए। यहां तक कि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली भी नष्ट हो गई। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों को लक्ष्य भेदने से रोक नहीं सका। इसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान जहां चीन के हथियारों और सुरक्षा तंत्र के भरोसे था, तो वहीं भारत ने (राफेल फाइटर को छोड़ दें) स्वदेशी हथियारों, मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम पर भरोसा किया और उसी का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। शुरुआती दिनों को छोड़ दें, तो बाद में विदेशी मीडिया ने भी भारतीय हमलों से पाकिस्तान के नुकसान को सही माना। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जीवन रक्षक प्रणाली पर है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा देश आंतरिक कलह और उग्रवाद से ग्रस्त है। पाकिस्तानी सेना ने देश के सबसे लोकप्रिय नेता (इमरान खान) को जेल में डाल रखा है। दुनिया को दिखाने के लिए एक कठपुतली गठबंधन सत्ता में है।

इन सबसे पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त हो गई है। लगभग रोजाना पाकिस्तान में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना की लोकप्रियता दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है। पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकार एवं बुद्धिजीवी मानते हैं कि जनरल मुनीर इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए कभी धर्म का सहारा लेते हैं, तो कभी भारत के खिलाफ उन्माद फैलाते हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा कहते हैं, 'इस हमले के पहले पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। अब देश में माहौल बदल गया है। निश्चित रूप से यह भारत के हालिया हमले के कारण हुआ है।' 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। 11 मई को शाहबाज सरकार ने 'शुक्रिया दिवस' मनाया। इस पर पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने कहा, 'भारत ने हमारे पंजाब और सिंध प्रांतों के शहरों में ड्रोन हमले किए।

भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत

	भारत	पाकिस्तान
रक्षा बजट	6.8 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26)	64,082 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25)
सैन्यकर्मी	51,37,550	17,04,000
सक्रिय कर्मी	14 लाख	6.5 लाख

वायुसेना

2,229 विमान (1,672 तैयार) हैं।

1,399 विमान (797 तैयार) हैं।

	भारत	पाकिस्तान
युद्धक टैंक	3982	2687
तोपखाना	1922	1842
लड़ाकू हेलिकॉप्टर	39	43
सहायक हेलिकॉप्टर	700	328
परिवहन विमान	708	2961
बख्तरबंद लड़ाकू वाहन	3200	2600

नौसैनिक बल

भारत

कुल 293 परिसंपत्तियां हैं, जिनमें दो विमान वाहक पोत, 13 विध्वंसक पोत, 14 फ्रिगेट, 18 कोर्वेट, 135 गश्ती पोत और 18 पनडुब्बियां हैं।

पाकिस्तान

कुल 121 संपत्तियां हैं, जिनमें नौ फ्रिगेट, 69 गश्ती जहाज, नौ कोर्वेट, आठ पनडुब्बियां और तीन माइन वारफेयर हैं। उसके पास कोई भी विमान वाहक या विध्वंसक पोत नहीं है।

रावलपिंडी के स्टेडियम से लेकर अटक तक, भारतीय ड्रोन सैकड़ों की संख्या में आए और जहां चाहा, वहां हमला किया। उससे हुआ नुकसान पाकिस्तान में दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो भी जवाबी हमले किए, उनसे भारत के किन-किन शहरों में नुकसान हुआ, इसके कोई सबूत नहीं हैं।'

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ सैन्य हमले नहीं किए, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने का पूरा प्रयास किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल दुनिया के सभी प्रमुख देशों के समकक्षों से बातचीत करते रहे हैं। दुनिया को आतंकी हमलों की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही स्पष्ट संदेश दिया गया कि आतंकवाद से अपने देश की सुरक्षा का हमें पूरा अधिकार है। भारत उसी अधिकार का प्रयोग करके आतंकवादियों पर कार्रवाई जरूर करेगा। इसलिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया को पता था कि भारत आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा। भारत ने सात मई की रात आतंकी ठिकानों पर हमले करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना यदि हमले नहीं करती तो सैन्य संघर्ष आगे नहीं बढ़ता। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले किए। उससे भारत का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तब पाकिस्तान अमेरिका की शरण में गया और उससे भारत से हमले रुकवाने के लिए कहा।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर बताते हैं, 'अमेरिकी विदेश मंत्री का फोन आया था। उन्होंने हमले रोकने को कहा था। तब हमने स्पष्ट कह दिया था कि इसके लिए पाकिस्तान को भारत से बात करनी होगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके हमले रोकने का आग्रह किया। उसके बाद ही हमने हमले रोके।' दोनों देशों के बीच हमले रोकने की बात फाइनल हो गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान की ओर से सीज फायर लागू करने का इंतजार कर रहा था कि तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एक्स' पर भारत-पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी। विपक्षी दल अब इसे ही सरकार को घेरने के लिए मुद्दा बना रहे हैं। देश के विपक्षी दल हों या अमेरिका या फिर पाकिस्तान, इन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम अपने संबोधन में जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने आक्रामक संबोधन में बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान ने ही भीख मांगी थी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक विराम था और आतंकी कार्रवाई का कोई भी नया मामला और भी मजबूत जवाबी कार्रवाई को जन्म देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भूगोल कोई बाधा नहीं बनेगा। भारत उन्हें कहीं भी खदेड़ सकता है और आतंक के मामले में जितना भी संभव होगा, उतना आगे बढ़ सकता है। मोदी सरकार की पहले नीति थी कि आतंक और बातचीत एक साथ संभव नहीं है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने इस नीति को और कठोर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'व्यापार और बातचीत आतंक के साथ नहीं चल सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।' प्रधानमंत्री की इस बात ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखेगा, जब तक पाकिस्तान अपने तौर-तरीके नहीं बदल लेता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर मसले पर अब सिर्फ पीओके के बारे में बात होगी। भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के बाद भारत अब अपनी कूटनीति को और मजबूत करने में लगा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर पहुंचा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को प्रमुख साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में भेजा है। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

चीनी हथियार के सहारे पाकिस्तान

पाकिस्तान के पास अपना कोई स्वदेशी हथियार नहीं है। वह चीन के हथियारों पर निर्भर है। जिस तरह से भारतीय वायु सेना और मिसाइलों ने पाकिस्तान और पीओके में तबाही मचाई है, उससे चीनी हथियारों और रडार सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' से चीन के अरबों डॉलर के रक्षा उद्योग का भी एक तरह से युद्ध परीक्षण हो गया। पाकिस्तान के पास अपना कोई स्वदेशी हथियार नहीं है। वह चीन के हथियारों पर निर्भर है। जिस तरह से भारतीय वायु सेना और मिसाइलों ने पाकिस्तान और पीओके में तबाही मचाई है, उससे चीनी हथियारों और रडार सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान कई रक्षा विशेषज्ञों ने यहां तक कह दिया कि इस युद्ध में हमें चीनी सैन्य तकनीक और हथियारों की क्षमता का पता लग गया है और चीनियों को भी भारतीय क्षमता का एहसास हो गया होगा। अब चीन भारत से भिड़ने की गलती नहीं करेगा।

सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों के रक्षा विशेषज्ञ भी चीनी हथियारों पर सवाल दाग रहे हैं। एशिया-पैसिफिक फाउंडेशन के निदेशक सज्जन गोहेल ने सीएनएन को बताया कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में अपने टारगेट को सफलता से मार गिराया है। यह बताता है कि

चीन द्वारा निर्मित पाकिस्तानी रडार और मिसाइल रक्षा उन्हें रोकने में विफल रहे। अगर चीनी मूल के रडार या मिसाइल सिस्टम भारतीय हमलों का पता लगाने या उन्हें रोकने में विफल रहे हैं, तो यह चीनी हथियार उद्योग के लिए बुरा संकेत है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के आंकड़ों को मानें, तो 2014 से 2024 के बीच चीन ने पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर से अधिक के हथियार बेचे हैं। यह पाकिस्तान के सैन्य आयात का 80 प्रतिशत से अधिक है। पाकिस्तान को पहले अमेरिका से हथियार

पाकिस्तान को चीन से मिले हथियार एवं रडार

वीटी-4 टैंक (हैदर)

संख्याः 176

लागतः 859 मिलियन डॉलर

अनुबंधः 2018 और 2020 में पाकिस्तानी सेना में शामिल। ये भारत के टी-90 एमएस और अर्जुन बेड़े का मुकाबला करने के लिए तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक हैं।

एसएच-15 155 एमएम हॉवित्जर

संख्याः 236

लागतः 500 मिलियन डॉलर

अनुबंधः 2019 में और 2022 तक इसे शामिल किया गया। यह 50 किमी तक मार कर सकता है। यह भारत के के-9 वज्र सिस्टम का मुकाबला करने के लिए खरीदा गया है।

एलवाई-80 एयर डिफेंस एचक्यू-16

संख्याः 9

लागतः 599 मिलियन डॉलर

अनुबंधः 2013 में और इसे 2017 में शामिल किया गया। यह 40 किमी दूर और 15 किमी ऊंचाई तक मार कर सकता है।

जेएफ-17 थंडर

विशेषताः यह चीन के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके ब्लॉक-2 को 2015-16 तक वितरित और ब्लॉक-3 को 2022 तक शामिल किया गया। इसमें चीनी एईएसए रडार, पीएल-15 लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को लादा जा सकता है।

जे-10सी 'फायरबर्ड'

मात्राः 25

लागतः 1-1.5 बिलियन डॉलर

अनुबंधः 2021, 2022 में इसे शामिल किया गया। यह 4.5 जनरेशन जेट है और भारत के राफेल को टक्कर देने का दावा करता है।

मुख्यालय-9

शामिलः 2021 (मुख्यालय-9-पी), 2022 (मुख्यालय-9 बीई, एफडी-2000 संस्करण)

यह प्रमुख शहरी और रणनीतिक लक्ष्यों को कवर करता है। मिसाइलों और विमानों के खिलाफ रक्षा में सुधार करता है।

चीनी यूसीएवी

प्रकारः सीएच-4 'रेनबो', विंग लूंग-2

उपयोगः टोही, सटीक हमले

काराकोरम ईगल (जेडडीके-03 एडब्ल्यूएसीएस)

मात्राः 04

लागतः 278 मिलियन डॉलर

शामिलः 2015

हैंगर-क्लास पनडुब्बियां (टाइप 039 बी-041)

मात्राः 08

लागतः 4-5 बिलियन डॉलर

अनुबंधः 2016 में और इसे 2023-24 (04 पनडुब्बियां) में शामिल किया गया। शेष 04 को वर्ष 2028 में शामिल किया जाएगा।

टाइप 054 ए-पी फ्रिगेट (तुगरिल-क्लास)

मात्राः 04

शामिलः 2021-2023

विशेषताएंः उन्नत एंटी-शिप और एंटी-एयर हथियार

अजमत-क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट

मात्राः 04

मिसाइलः प्रति पोत 8 सी-802ए एंटी-शिप

मिला करते थे। 2010 तक अमेरिका, पाकिस्तान का मुख्य रक्षा साझीदार था। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के दोहरे चरित्र से निराश होता रहा है।

खासकर, अफगान तालिबान का समर्थन, हक्कानी नेटवर्क को पनाह देना, ओसामा बिन लादेन प्रकरण और सीमा पार हमलों के लिए अपने द्वारा तैयार किए गए समूहों की अनदेखी ने अमेरिका को पाकिस्तान से दूर कर दिया। 2016 तक वाशिंगटन ने हथियारों की बिक्री बंद कर दी। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों से संबंधों (खासकर, ओसामा बिन लादेन प्रकरण) और

वहां के शासन पर सेना का वर्चस्व रहने के कारण उसने हथियार बेचने बंद कर दिए। चीन ने इसी कमी को पूरा किया। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीनी मदद मिलने की बात को चीन ने नकार दिया है। एक तरफ पाकिस्तान चीनी हथियारों पर निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ भारत किसी एक देश से हथियार नहीं खरीदता है। भारत ने अपने हाल के हथियारों का आधे से अधिक हिस्सा फ्रांस, इजरायल और अमेरिका जैसे देशों से खरीदा है। साथ ही स्वदेशी हथियारों का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

आईपीएल 2025 फाइनल

जीत के बाद जश्न में भगदड़ मचने से 11 मौत

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद फैंस खुशी से झूम उठे थे और जब उनकी टीम ट्रॉफी पहुंची तो ये जश्न मातम में बदल गया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड में शामिल होने पहुंचे फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और वहीं मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई. इसे लेकर आरसीबी की तरफ से जो बयान आया वो बेशर्मी भरा था। उसमें कहा गया कि जश्न मनाने आए फैंस से एक दूसरे का ध्यान रखने को कहा गया था लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटना हो गई। इतने बड़े आयोजन को बिना ठोक इंतजाम के कराया गया और आरसीबी इसको लेकर अपने इंतजाम की जगह लोगों पर ही दोष डाल रही है। प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को क्रिकेटप्रेमियों की भावनायें समझनी चाहिये लेकिन कुप्रबंधन पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारे हाथ में है, हम उस पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हर स्तर पर सहयोग कर रही है लेकिन यह लोगों की भावनायएं थीं। जीत के जश्न में एक दूसरे का ध्यान रखने के संदेशों के बावजूद ऐसे हालात बन गए। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हमें लोगों की भावनाओं को समझना होगा. उन्होंने संयम के साथ इस जीत के लिए 18 साल इंतजार किया है। हमें इस कमजोरी और भावनाओं के लिए उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए।

भगदड़ के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा

आरसीबी प्रबंधन ने विक्ट्री परेड को लेकर कैसी योजना बनाई थी इसका पता तो भगदड़ मचने से हुए मासूम फैंस की मौत से पता चल गया। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जब टीम के जश्न में शामिल होने वाले फैंस अपनी जान गंवा बैठे और 11 लोगों की मौत हो गई फिर भी ये कार्यक्रम जारी रखा गया। इसको रोकने की जगह टीम ट्रॉफी लेकर स्टेज पर पहुंची और फिर पूरे स्टेडियम में इसको घुमाया भी गया। जबकि बाहर इसी टीम के कई फैंस की जान चली गई।

आईपीएल चेयरमैन अरूण धूमल ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस त्रासदी के बारे में पता चला, उन्होंने आयोजकों से कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस भी जांच की

जरूरत होगी, वह की जायेगी। यह बीसीसीआई का आयोजन नहीं था। यह दुखद और त्रासद है। जश्न यूं त्रासदी में बदल गया। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदनायें।

धूमल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था या नहीं। प्रशंसकों को बुलाया गया था या वे खुद आये थे। जब मैं आरसीबी अधिकारियों से बात कर रहा था तो स्टेडियम के भीतर इतना शोर था। उन्हें शायद पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जब मैने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कार्यक्रम तुरंत बंद कराया जायेगा।

मृतकों के परिवारों को किया 10 लाख देने का ऐलान

आईपीएल चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने टीम की आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को दस दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। विराट कोहली और टीम की एक झलक पाने के लिये लाखों की तादाद में प्रशंसक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एकत्र हो गए जिससे 11 लोगों की मौत हो गई थी । आरसीबी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि बेंगलुरू में कल हुए हादसे से आरसीबी परिवार दुखी है। आरसीबी ने 11 मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है इसके अलावा आरसीबी केयर्स कोष भी बनाया जायेगा जिसके जरिये इस हादसे में घायल हुए प्रशंसकों की मदद की जायेगी।' इस हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं ।

कमल हासन, आर माधवन, सुनील शेट्टी ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

अभिनेताओं कमल हासन, आर माधवन और सुनील शेट्टी समेत कई प्रसिद्ध हस्तियों ने बेंगलुरू में मची भगदड़ की घटना में लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया है। 'इंडियन प्रीमियर लीग' (आईपीएल) में 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु' (आरसीबी) की जीत के जश्न में भाग लेने के लिए बुधवार को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के जुटने के बाद मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। हासन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर इस घटना को ''दिल दहला देने वाली त्रासदी'' बताया। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत दुखी हूं और दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ितों के परिवारों के साथ हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। माधवन ने कहा कि यह बहुत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। कृपया जिम्मेदार बनें एवं सुरक्षित रहें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। शेट्टी ने 'एक्स' पर लिखा कि खुशी का एक पल, अकल्पनीय घटना में बदल गया। बेंगलुरु में जान गंवाने वालों के बारे में सुनकर दिल दहल गया। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजन खो दिए। अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने भी इस घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपनों को खोना वाकई दुखद है, खासकर उस समय जब क्रिकेट में सामूहिक खुशी का पल होना चाहिए था। सोनू सूद ने भी 'एक्स' पर पोस्ट किया कि बेंगलुरु में आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान हुई त्रासदी से दिल दहल गया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों और सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता हूं। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

- **180 मेगावाट से 8140.04 मेगावाट तक की यात्रा :** अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 30 नवीकरणीय ऊर्जा पावर स्टेशनों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति ।
- **सुदृढ़ वित्तीय प्रदर्शन:** अपनी स्थापना के बाद से निरंतर सुदृढ़ परिणाम प्रदर्शित कर रही है ।
- **15 सक्रिय परियोजनाएं :** संधारणीय भविष्य के लिए, लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का निर्माण कर रही है ।
- **एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देना:** वर्ष 2032 तक 23,000 मेगावाट और वर्ष 2047 तक 50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य ।
- **भारत की दो सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण:**
  - दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना: 2,880 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश में ।
  - सुबनसिरी लोअर परियोजना: 2,000 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश और असम में ।
- **नवरत्न का दर्जा:** कार्यनीतिक महत्व को मान्यता देते हुए 30 अगस्त, 2024 को प्रदान किया गया ।
- **भविष्य के लिए विजन:** एनएचपीसी संधारणीय ऊर्जा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन के प्रति समर्पित है ।

एनएचपीसी

स्वर्ण

आ

हम सब मिलकर हरित ऊर्जा में ने

https://www.nhpcindia.com

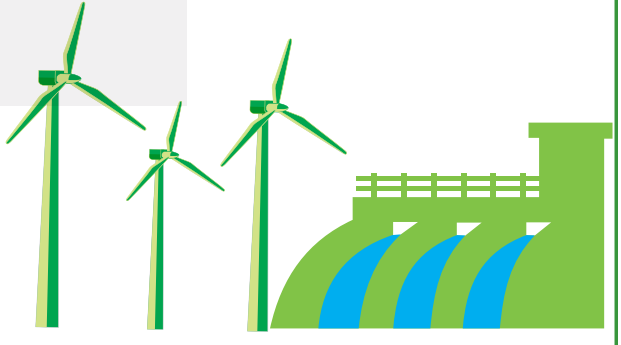

निहित शक्ति
एनएचपीसी
NHPC
1975 से
का हरित ऊर्जा नेतृत्व
जयंती वर्ष
की विरासत का उत्सव मनाएं !
एनएचपीसी
NHPC
एक नवरत्न कंपनी
Join us:

मोदी ने किया चिनाब ब्रिज का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ-साथ उन्होंने देश के पहले केबल-स्टेड रेल पुल अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने चिनाब पुल का निरीक्षण किया और सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छाशक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी-ए-कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धाभाव से कहते आए हैं- कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामुला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही दो नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली हैं। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्टस जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया, वो भी बोले थे कि जब वो सातवीं-आठवीं में पढ़ते थे, तब से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम हैं ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे।

पीएम ने कहा कि रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण हैं। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसलों को जीया है। चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पैरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं। और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी प्वाइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं, ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी, भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्ज्वल भविष्य की सिंहगर्जना है। ये दिखाता है, विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। पीएम ने कहा कि चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की, दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो

बढ़ेगा ही, इकॉनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी, दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी, अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हों या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना-जाना भी बहुत आसान होगा। पीएम ने कहा कि मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन देखी थी, जो गांव से बाहर गए थे। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा, कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने से गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने-जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही, उस बिटिया ने कहा- अब मौसम नहीं तय करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे, अब ये नई ट्रेन सेवा, हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग-अलग रत्न जम्मू-कश्मीर का सामर्थ्य हैं। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी-बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है, वो मुकुट मणि की तरह चमकता है।आप भलीभाँति जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा हूं, ग्रामीण इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू-कश्मीर के विकास में जुटा हूं। पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत, दुनिया के बड़े नॉलेज हब्स में से एक, हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां क्क्ळ, क्क्ट, अक्क्टर और ठक्ळ जैसे संस्थान हैं। जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है।

जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 पहुंच गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां पढ़ाई के साथ-साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। बीते कुछ सालों में ही, दो स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले पाँच वर्षों में यहां सात नए मेडिकल

कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू-कश्मीर में अब ट्इइर सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान-पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है, उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है, उसके लिए भारत के कोने-कोने से, माता वैष्णों देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़ाकर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है।

सरकार के 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा-एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल, गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है, हमारी बहनों को, बेटियों को, उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे ढाई करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है, महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है।

11 साल में 25 करोड़ गरीब, गरीबी से बाहर निकले

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने, गरीबी को हमारे ही गरीब भाई-बहनों ने, गरीबी के खिलाफ जंग लड़ी और 25

करोड़ गरीब, गरीबी को परास्त करकर के, वियजी होकर के, गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग अगले पिछले की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है, उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं, वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7-7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे। ये मेरे दलित भाई-बहन हैं, ये मेरे आदिवासी भाई-बहन हैं, ये मेरे पिछड़े भाई-बहन हैं, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी-झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार हैं, जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। वन रैंक वन पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।

हम यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं

हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं। और इसका एक अहम जरिया है- टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश, मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं वो ऐसा देश है, गरीब की रोजी-रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इन्सानियत और कश्मीरियत, दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट्स पर हमला किया। वो टूरिज्म, जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से, जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई

दुकान-ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत-मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देख रेख कर सके, इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया।

जम्मू कश्मीर का नौजवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का बना चुका है मन

पाकिस्तान की इस साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनियाभर की आतंकवादी मानसिकता को, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है, जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो-दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था। अस्पताल तबाह किए। जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सकें, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू-कश्मीर ने इतनी बबार्दी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था, आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू-कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू-कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देखकर के खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं, इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू-कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू-कश्मीर के आप सभी लोगों को, और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा, यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रूकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा।

6 मई की रात पाक के आंतकियों पर कयामत बरसी थी

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 6 जून है, याद कीजिए एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले, 6 मई की वो रात, पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा, तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत, पाकिस्तान में सैंकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाईं थीं, वो कुछ मिनटों में ही खंडहर में बदल गईं हैं। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था, और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के, दूसरे जिलों के लोगों पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल-अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया, वो हर देशवासी ने देखा है।

इसलिए अपने परिवारजनों, उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2 हजार से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है, कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में, मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्सट्रा धनराशि मिलेगी। हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है, इस दौरान करीब दस हजार नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे ये बताते हुए खुशी है, कि जम्मू और कश्मीर डिविजन के लिए दो बॉर्डर बटालियन बनाई गई है।

सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वहीं हर भारतवासी को दोहराना है

आज मैं जम्मू-कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है, सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू-कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए, इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल, भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई देंगे। पिछले दस वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है, दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

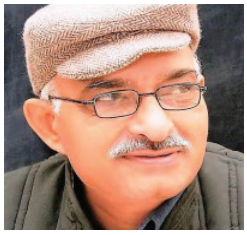

आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का पैगाम

प्रभात कुमार रॉय

भारत पाक सैन्य संघर्ष के उपरांत कुछ यक्ष प्रश्न उठ खड़े हुए हैं? पहला यक्ष प्रश्न है कि भारत का एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 30 से अधिक प्रमुख देशों में आखिरकार क्यों भेजा गया? दूसरा यक्ष प्रश्न है आखिरकार मात्र चार दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान से भारत को युद्ध विराम क्यों करना पड़ गया? तीसरा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या भारत की सैन्य तैयारियों में पाकिस्तान को निर्णायक तौर पर पराजित करने के लिए अत्यंत कमी महसूस की गई ?भारत पाक सैन्य संघर्ष में युद्ध विराम के तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों क्रमश बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, जदयू, बीजेडी, सीपीएम, शिवसेना, और आप पार्टी का एक संयुक्त सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के तीस से अधिक प्रमुख देशों के शीर्ष लीडरों को भारत का कूटनीतिक पैगाम देने के लिए भेजा गया। भारत का प्रबल पैगाम है कि पाकिस्तान द्वारा प्रेरित और पोषित जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध वस्तुत भारत का दृष्टिकोण और रणनीति जीरो टॉलरेंस से ओतप्रोत है। भारत वस्तुतः जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध विगत 36 वर्षों से निरंतर विकट संग्राम कर रहा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में अंजाम दिए गए नृशंस आतंकवादी आक्रमण का सैन्य प्रतिशोध लेने के लिए वस्तु पाकिस्तान हुकूमत एवं सेना की कयादत में संचालित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने के लिए भारत ने 7 मई से 10 मई तक सैन्य ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया। सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी सरकार के प्रमुख लीडरों से मुलाकात की गई। भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख चेहरे रहे, बीजेपी के विजयंत पांडा, रवि शंकर प्रसाद, अपराजिता सारंगी, अनुराग ठाकुर, जदयू के संजय कुमार झा, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, श्रीकांत एकनाथ शिंदे और एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके की सांसद कनिमोझी, शिवसेना की प्रियंका चतुवेर्दी । सांसद बैजयंत जय पांडा सऊदी अरब के शेख लीडरान से मुखातिब हुए।

डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ग्रीस की लीडरशिप से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका एवं अन्य अफ्रीकी देशों के लीडरों से मिलने पहुंची नेशनल कांग्रेस पार्टी की सांसद की सुप्रिया सूले। इटली की राजधानी रोम और फ्रांस की राजधानी पेरिस में शीर्ष लीडरों से मुलाकात की सांसद रवि शंकर प्रसाद ने। मनीष तिवारी ने मुलाकात की मध्य एशिया और यूरोप के लीडरों से। सलमान खुर्शीद ने मुलाकात की दक्षिण एशिया के देशों के लीडरों से विशेष कर दक्षिण कोरिया जापान और सिंगापुर के लीडरों से। अमेरिका तथा लैटिन अमेरिकन के देशों का कूटनीतिक दौरा अंजाम दिया कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने।

यक्ष प्रश्न है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आखिरकार ऐसा कूटनीतिक निर्णय क्यों लिया गया कि भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के तीस से अधिक प्रमुख देशों में भेजा गया? जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध अंजाम दी गई अपनी शानदार सैन्य कार्यवाही के विषय में विश्व भर को अवगत कराने की भारत सरकार को आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई? आखिरकार संसदीय प्रतिनिधिमंडल के केवल 10 दिनों के कूटनीतिक दौरे की वास्तविक उपलब्धि क्या रहेगी? दरअसल भारत को विश्व भर प्रमुख राष्ट्रों से पाकिस्तान के विरुद्ध जारी सैन्य संघर्ष के दौरान जबरदस्त समर्थन की उम्मीद थी। विश्व पटल पर वैश्विक जिहाद आतंकवाद की सबसे बड़ी निर्माणशाला और पनाहगाह कहे जाने वाले पाकिस्तान को अपना प्रबल समर्थन प्रदान करने के लिए तुर्की, अजरबैजान और अमेरिका स्पष्ट तौर पर सामने आ गए। भारत का प्रबल समर्थन करने में इस दफा रूस द्वारा कदाचित कोई गहन दिलचस्पी प्रकट नहीं की गई। सन- 1947 से सदैव ही कश्मीर विवाद के प्रश्न पर भारत का एक तरफा सक्रिय समर्थन करने वाले रूस ने भी इस दफा दोनों संघर्षरत पक्षों के मध्य सुलह कराने के लिए केवल अपनी मध्यस्थता प्रस्तुत कर दी।पाकिस्तान द्वारा प्रेरित और

पोषित जिहादी आतंकवादियों के द्वारा कम से कम 60 दफा गहरे जख्म झेलने वाला अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आया। चीन द्वारा तो खुलकर सार्वभौमिकता के नाम पर पाकिस्तान का प्रबल समर्थन किया गया। पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लिए विश्व पटल पर बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका रहा। संभवत यही सबसे बड़ा कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के 30 से अधिक प्रमुख देशों में भेजा गया, ताकि भारत के पक्ष को कूटनीतिक तौर पर विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। क्वॉड्रिलैटरल डायलॉग (क्वाड) हालांकि कोई रणनीतिक मोर्चा नहीं है, किंतु क्वाड में चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध भारत एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। दुर्भाग्य से क्वॉड द्वारा भी सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के प्रति नैतिक समर्थन तक व्यक्त नहीं किया गया। तकरीबन 48 वर्ष पहले जब सन् 1971 में पाकिस्तान और भारत के मध्य एक बड़ी निर्णायक बांग्लादेश जंग हुई थी। उस ऐतिहासिक दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा महान-स्वतंत्रता सेनानी और सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक सर्वदलीय कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भेजा गया था। आजादी हासिल होने के तत्पश्चात भारतीय संसद द्वारा दो अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट्री संगठनों में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी गई है। पहला पार्लियामेंट्री संगठन है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन (आईपीयू) और दूसरा है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीएम) । विश्व पटल पर अपनी कूटनीतिक शक्ति को

बढ़ाने के लिए भारत को निरंतर प्रयास करना होगा। खासतौर पर अपने परंपरागत रणनीतिक साझेदारी रूस को अपने पक्ष में लाने के लिए गहन कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कयादत कर रहा था और और शीत युद्ध के दौर में किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं था, तब भी सोवियत संघ रणनीतिक रूप से भारत के साथ दमदार ढंग से खड़ा था। फिर आखिर कहां कूटनीति चूक हो गई है कि रूस पाकिस्तान को अपना राजनीतिक पार्टनर करार देने लगा है।

दूसरा यक्षप्रश्न है कि आखिरकार ऐसी कौन सी कूटनीतिक मजबूरी थी कि भारत को चार दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद ही पाकिस्तान से युद्ध विराम करने पर विवश होना पड़ा? भारत जिहादी आतंकवाद के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की ऐलान करता रहा है। मात्र चार दिनों की सैन्य कार्रवाई से आतंकवाद को पाकिस्तान की सरजमीं से समाप्त करना एकदम नामुमकिन है। आतंकवाद को निर्णायक तौर पर समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की फौज को निर्णायक तौर पर सन् 1971 की जंग की तरह पुनः एक दफा और पराजित करना होगा। पाकिस्तान में जिहादी आतंकवाद दरअसल पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों और इनके तहत काम करने वाली आईएसआई के संरक्षण और परिपोषण द्वारा पल्लवित होता रहा है। पाकिस्तान की सरजमीं से जिहादी आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सिर्फ आतंकवादियों को कत्ल करना ही काफी नहीं है वरन संपूर्ण तंत्र को नष्ट करना अति आवश्यक है जोकि जिहादी आतंकवादियों का निर्माण करता है और उनको संचालित करता है। भारत और पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर संघर्ष विराम का ऐलान किया जाता, उससे कहीं पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर दिया और दावा पेश कर दिया कि उनकी हुकूमत ने दोनों मुल्कों में मध्यस्थता अंजाम दी। अमेरिकी कूटनीति के दबाव में दोनों देश तुरंत और पूर्णतः संघर्ष विराम करने के लिए सहमत हो गए। दूसरी और भारत सरकार का कहना है कि युद्ध विराम पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) की पहल पर अंजाम दिया गया। भारत सरकार द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम कराने के कूटनीतिक दावे का खंडन तो कदाचित नहीं किया गया, लेकिन प्रेजिडेंट ट्रंप के दावे की बाकायदा पुष्टि भी नहीं की गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध विराम की कूटनीतिक पहल से भारत सरकार की स्वतंत्र विदेश नीति पर क्या एक प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो गया है?

तीसरा यक्ष प्रश्न है कि क्या आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कार्य नीति का बाकायदा ऐलान करने वाली भारत सरकार के पास पाकिस्तान फौज को निर्णायक तौर पर परास्त करने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति विद्यमान नहीं थी? एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने फरमाया कि महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम खरीद फरोख्त और उसकी डिलीवरी में हो रहे अतिशय विलंब पर वायु सेना में हो रही गहरी चिंता का इजहार किया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट को वक्त से पूरा न होने का भी उल्लेख किया और घरेलू डिफेंस डील पर भी कुछ बातें पेश की। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना हार्डवेयर के अभाव से लंबे वक्त से जूझ रही है। भारतीय वायु सेना के पास अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर विमान विद्यमान नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर विमान के घरेलू उत्पादन के लिए मंजूरी तो प्रदान कर दी है। लेकिन अभी तो स्टेल्थ फाइटर विमानों का निर्माण होने और फिर उसकी तैनाती होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। अनेक रक्षा विशेषज्ञों का कथन है की भारतीय सैन्य रक्षा सामग्री की खरीदारी और डिलीवरी में एक लंबा अंतराल होने के कारण भारतीय सेना में हताशा निरंतर गति से बढ़ रही है। एयर चीफ मार्शल का बयान इस तथ्य को प्रकट करता है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अंजाम दिए गए आतंकवादी आक्रमण और 7 मई को पाकिस्तान के अंदर भारतीय वायु सेवा द्वारा अंजाम दिए गए हवाई हमलों के तत्पश्चात दोनों देश युद्ध के लिए आमने-सामने आ गए थे। 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद भी दोनों ओर से ड्रोन हमले और सीमा पर जबरदस्त गोलाबारी हुई। इस चार दिवसीय सैन्य झड़प के बाद भारत में रक्षा तैयारियों को अत्यंत तीव्रता लाने की चर्चा ने बहुत जोर पकड़ लिया है। रक्षा विशेषज्ञों का विचार है कि भारत की रक्षा तैयारियों में और अधिक तेजी लाने की जरूरत के संदर्भ में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान को स्पष्ट तौर पर समझा जाना चाहिए। सन् 1993 में भारतीय संसद द्वारा एकमत से पारित प्रस्ताव को अमली जमा पहनाना है कि संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत को अपना आधिपत्य स्थापित करना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत को अपनी सैन्य तैयारी अत्यंत तेज कर देनी चाहिए। ◆◆◆

साहिल शर्मा, हिमाचल ब्यूरो प्रमुख

सीबीआई करेगी नेगी प्रकरण की जांच

पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। 10 मार्च को अचानक लापता हुए नेगी का शव 18 मार्च को बरामद किया गया था।

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेगी परिवार की मांग पर इस मामले की एसआईटी के बजाय सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन निदेशक देशराज एवं तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा को नामजद कर लिया है। बहुचर्चित गुड़िया प्रकरण के बाद यह दूसरा मामला है, जिसे लेकर इस पहाड़ी प्रदेश के दो प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। विपक्ष पहले दिन से ही सरकार को घेरने की कवायद में जुट गया, जिसके चलते पहाड़ की ठंडी वादियों में मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही सियासी माहौल भी गर्मा गया है। इस तपिश की आंच अब जांच में जुटे अधिकारियों पर आई है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर अपना दामन पाक-साफ दिखाते हुए नेगी परिवार को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं, मौत के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की आपसी खींचतान और कथित अनुशासनहीनता के आरोप में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।

विमल नेगी की मौत का मामला अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पास है। उसने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन प्रदेश में इस मामले को लेकर एक और ही खेल शुरू हो गया है। सुक्खू सरकार ने जांच से जुड़े आला अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस ओंकार शर्मा, डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा एवं

मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप है कि दिवंगत चीफ इंजीनियर विमल नेगी का परिवार जांच एसआईटी के बजाय सीबीआई को सौंपने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहा था। इसके लिए परिवार की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी भी मामले में पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। ठाकुर का कहना है कि नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या के नजरिये से भी देखा जाना जरूरी है। जिन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा यह मामला है, उनमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। कई नेताओं एवं आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिमला और ऊना के पेखु वाला सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए के घोटालों को दबाने का प्रयास हुआ है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली जांच है, जिसमें पुलिस के लोग सबूत जुटाने के बजाय उन्हें नष्ट कर रहे थे। नेगी की मौत पर मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा सदन से लेकर सड़क तक बोला गया हर झूठ बेनकाब हो गया है। विमल नेगी की पत्नी किरण ने हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री सुक्खू को पत्र लिखकर गुहार लगानी पड़ी। पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय गृहमंत्री को भी भेजी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोलते रहे कि नेगी के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है।

एसपी शिमला संजीव गांधी को अवकाश पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि ओंकार शर्मा ने इस मामले की जो जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी, उससे प्रदेश सरकार खुश नहीं थी। इस वजह से अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से जनजातीय विकास, राजस्व, जलशक्ति, गृह एवं विजिलेंस आदि सारे विभाग वापस लेकर अन्य अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। शर्मा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसी प्रकार प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक का कार्यभार डीजी विजिलेंस अशोक तिवारी को सौंप दिया है।

> आपसी खींचतान से प्रदेश सरकार की फजीहत कराने वाले अधिकारियों डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा एवं एसपी शिमला संजीव गांधी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह को एसपी शिमला का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

आपसी खींचतान से प्रदेश सरकार की फजीहत कराने वाले अधिकारियों डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा एवं एसपी शिमला संजीव गांधी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह को एसपी शिमला का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रदेश सरकार की यह कार्रवाई कई सवालों को सिर उठाने का मौका दे रही है। विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। भाजपा विधायक दल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में राज्यपाल से मिलकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने एसपी शिमला को बर्खास्त करने के साथ-साथ पावर कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है।

प्रेस वार्ता से उलझा मामला

हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश देने के साथ ही पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। इसके बाद एसपी शिमला संजीव गांधी ने सेवा नियमों एवं प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया। उन्होंने डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा एवं अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए। गांधी ने कहा कि डीजीपी द्वारा अदालत में गलत हलफनामा दाखिल किया गया। विमल नेगी का पेन ड्राइव जांच में शामिल नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला वापस लौटने पर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने सीबीआई जांच का समर्थन किया। यही नहीं, सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर इस मामले को लेकर झूठ बोलने और राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके बाद सरकार ने जांच में जुटे अधिकारियों एसीएस ओंकार शर्मा, डीजीपी अतुल वर्मा एवं एसपी शिमला संजीव गांधी को अवकाश पर भेजकर उनका कार्यभार दूसरे अधिकारियों को सौंप दिया।

अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं और प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं प्रवक्ताओं के बीच वाकयुद्ध जारी है। भाजपा पावर कॉरपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रही है। वहीं सत्तापक्ष भाजपा पर इस मामले को लेकर राजनीति करने और राज्यपाल को ज्ञापन देने में जल्दबाजी का आरोप लगा रहा है। खैर, अब यह मामला सीबीआई के पास है और नेगी परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन, आने वाले दिनों में हिमाचल की ठंडी वादियों में मौसम के साथ-साथ सियासत का पारा भी चढ़ा रहेगा। ◆◆◆

सतपाल सिंह तंवर, दिल्ली ब्यूरो प्रमुख

100 दिन नीतियां बनाने और काम करने में बिताए : रेखा गुप्ता

मेरी सरकार ने 100 दिन दिल्ली की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने और काम करने में बिताए हैं। यह बात दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मौजूदा सरकार ईमानदार शासन, जन कल्याण और संरचनात्मक सुधारों पर आधारित है। गुप्ता ने कहा कि उनके प्रशासन ने झूठे वादे करने के बजाय नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं कर सकते। हम यमुना की सफाई और कूड़े के ढेरों को हटाने जैसे मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गुप्ता ने निजी विद्यालयों की फीस को विनियमित करने के लिए अध्यादेश लाने की अपनी योजना का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी माता-पिता पर अनुचित बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की वय वंदना योजना को सफल बताया, जिसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 लाख पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। सीएम ने आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हजारों लोग बदलाव की उम्मीद में आंदोलन में शामिल हुए लेकिन जो लोग सत्ता की भूख नहीं होने का दावा करते थे, वे इसी में डूब गए। जनता का भरोसा टूट गया। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम

में विशेष रूप से आमंत्रित अभिनेता अनुपम खेर से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार के शुरूआती 100 दिन छोटे अवश्य हैं, परंतु उनमें उठाए गए जनहित के ठोस और निर्णायक कदम दिल्ली की दिशा और दशा में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इस अवसर पर दिल्ली सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह केवल 100 दिनों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सरकार हर दिन, हर घड़ी

जनता की सेवा के लिए समर्पित है। हमारी सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, और अब हमारा अगला लक्ष्य है दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है। जब अभिनेता अनुपम खेर ने सीएम से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुण लेना हो तो क्या लेगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं समर्पण भाव अपनाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री के जीवन से मुझे राष्ट्र के प्रति समर्पण, दृढ़ संकल्प और सेवा भावना की प्रेरणा मिलती है। यही मूल्य मैं अपने कार्य में आत्मसात करने का प्रयास करती हूं। वहीं उन्होंने कार्यक्रम की शुरूआत में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ जीत है। यह नया भारत है, जो अब आतंकियों की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हर जवाब सटीक होगा, और हर वार निर्णायक होगा।

सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां

❑ यमुना की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ठोस कदम उठाए

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही यमुना की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इस दिशा में ठोस कदम उठाए। यमुना की सफाई के लिए 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई। यमुना पर फेरी और क्रूज चलाने का निर्णय, सभी नालों की सफाई शुरू की गई। वर्षों बाद 16 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाई गई। 7 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्वास और क्षमता वृद्धि कार्य पूरा किया गया। ओखला में 124 एमजीडी के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 8 परियोजनाओं के लिए 804 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, लगभग 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर और जल पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से जारी है।

❑ जलापूर्ति के लिए 1,167 जीपीएस से लैस टैंकर तैनात किए

सीएम ने बताया कि जल आपूर्ति की निगरानी के लिए एक आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, 1,167 जीपीएस-सक्षम जल टैंकर तैनात किए गए हैं, और 'डीजेबी वॉटर टैंकर एप की शुरूआत की गई है। साथ ही, दक्षिण दिल्ली में 70 नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिनसे लगभग 1.5 लाख लोगों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है।

❑ पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान और वय वंदना योजना को किया लागू

दिल्ली सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला लिया। इसमें हर गरीब को 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने वय वंदना योजना को लागू किया। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री में मिलेगा। वहीं दिल्ली की सेहत सुधारने के लिए 12 हजार 826 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण की योजना शुरू की गई। सभी सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खुलेंगे और सरकार अस्पतालों में 300 डायलिसिस मशीनें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही छह मोबाइल डेंटल वैन रोज 400 मरीजों का इलाज कर रही हैं।

❑ एक हजार नागरिकों पर 3 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा जो मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिला है, वह अत्यंत चिंताजनक है। पिछली सरकार ने 10 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा किया और आज हालात यह है की प्रति 1000 जनसंख्या पर एक भी बेड उपलब्ध नहीं है । उन्होंने आगे कहा कि डब्ल्यूएचओ के मानक के

अनुसार प्रति 1,000 व्यक्तियों पर कम से कम दो अस्पताल बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अगले आने वाले वर्षों में प्रति 1,000 नागरिकों पर कम से कम 3 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।

❑ स्कूल शिक्षा पारदर्शिता शुल्क निर्धारण और विनियमन बिल 2025 को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा मॉडल के नाम पर केवल प्रचार किया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने हाल ही में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता शुल्क निर्धारण और विनियमन बिल 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अव्यवस्थित शुल्क प्रणाली पर रोक लगाना है। इसके अलावा 125 स्कूल लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण किया गया है और 100 भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

❑ लैंडफिल साइट्स से कचरा हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को बनाया था। लेकिन अब लैंडफिल क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 30 हजार मीट्रिक टन कचरे का बायोमाइनिंग किया जा रहा है। भलस्वा और ओखला के कचरे के पहाड़ों को आगामी दो वर्षों में पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में दिल्ली में चार वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स सक्रिय हैं, और नरेला तथा गाजीपुर में दो नए संयंत्रों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, दिल्ली के होलम्बी कलां क्षेत्र में एक आधुनिक ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा।

❑ प्रदूषण से निपटने के लिए वर्षभर एक हजार स्प्रिंकलर संचालित रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली को गैस चेंबर में बदल दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता बनाते हुए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे वर्षभर 1,000 स्प्रिंकलर संचालित रहेंगे, जबकि एयर पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए 70 अत्याधुनिक मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही, सभी ऊंची इमारतों में स्मॉग गन लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर (देवी)योजना के अंतर्गत 460 इलेक्ट्रिक बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए शुरू कर दी गई हैं, और वर्ष के अंत तक 2,000 और ई-बसें सड़कों पर उतरेंगी।

❑ सौर ऊर्जा को दिया जा रहा है बढ़ावा

ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्लीवासियों को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सभी सरकारी भवनों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है, 'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के अंतर्गत 30 हजार तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का है।

❑ दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, होगा विकास

मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष द्वारा झुग्गियों को हटाए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन हम यह विश्वास दिलाते है कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि जब तक हर झुग्गीवासी को उसका पक्का मकान नहीं मिल जाता, तब तक वे अपनी वर्तमान झुग्गियों में ही रहेंगे,लेकिन पहले से कहीं बेहतर सुविधाओं और सम्मानजनक जीवन स्तर के साथ।

❑ महिलाओं 2500 रुपए की वित्तीय सहायता जरूर प्रदान करेंगे

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बताया कि 'महिला समृद्धि योजना' के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। महिला श्रमिकों के बच्चों की देखभाल के लिए 500 'पालना' केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त, दो नए 'सखी निवास' हॉस्टल बनाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली के प्रत्येक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, वीमेन पीसीआर सक्रिय किए गए हैं, और दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जा रही है। ◆◆◆

मैच फिक्स करने वाली टीम मैच तो जीत सकती है : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली इतने निचले स्तर पर पहुंच गई कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा, मैच फिक्स करने वाली टीम मैच तो जीत सकती है, लेकिन इससे जुड़े संस्थानों में भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा, 'चुनावों में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है।'

चुनाव आयोग का कहना है कि इस संबंध में आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को दिए अपने जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट कर दिए थे। वहीं, बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी बार-बार झूठ बोलकर राज्य के जनादेश का अपमान कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की आलोचना करते हुए 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'लोकसत्ता' समेत कई भारतीय अखबारों में विस्तृत लेख लिखे हैं । महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का दावा करते हुए राहुल गांधी ने 'धांधली के पांच चरण' बताए हैं।

राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ 5 आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली इतनी भयावह थी कि इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी आंकड़ों से इसके स्पष्ट सबूत सामने आए हैं।

राहुल गांधी का पहला आरोप

राहुल गांधी ने जो पहली आपत्ति जताई है, वह चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया को लेकर है।

राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ही '2-1' बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्त का चुनाव कर सकते हैं। इसमें तीसरा वोट हमेशा विपक्षी पार्टी के वोट को रद्द करने के लिए संभव था।

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश का पद एक कैबिनेट मंत्री को देने का निर्णय संदिग्ध है।

राहुल गांधी का दूसरा आरोप

राहुल गांधी का दूसरा आरोप फर्जी मतदाता सूची को लेकर है। इस आरोप में राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वे इस प्रकार हैं...

- 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता मतदान 8 करोड़ 98 लाख
- 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 9 करोड़ 29 लाख
- 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदाता मतदान 9 करोड़ 70 लाख
- ऐसे आंकड़े देते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा, 2019 से 2024 तक यानी पांच साल में 31 लाख वोटर बढ़े, तो 2024 में दो चुनावों, लोकसभा और विधानसभा के बीच के पांच महीने में 41 लाख कैसे बढ़ गए?

राहुल गांधी का तीसरा आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं की संख्या से अधिक वोट डाले गए।

उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदान के दिन शाम 5 बजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 58.22 प्रतिशत था. हालांकि, जब अगली सुबह अंतिम मतदान के आंकड़े घोषित किए गए, तो यह 66.05 प्रतिशत था।

ये आंकड़े देते हुए राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, अंतिम आंकड़ों में 7.83 प्रतिशत या करीब 76 लाख मतदाताओं की वृद्धि अभूतपूर्व थी।

राहुल गांधी का चौथा आरोप

राहुल गांधी ने इस लेख में फर्जी मतदान का मुद्दा भी उठाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ₹महाराष्ट्र में करीब 1 लाख मतदान केंद्र हैं। इनमें से सिर्फ 85 निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 12 हजार केंद्रों पर ही मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन 85 सीटों में से अधिकतर सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीती हैं। इस बार राहुल गांधी ने नागपुर के कामठी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में कामठी में कांग्रेस को 1 लाख 36 हजार वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1 लाख 19 हजार वोट मिले। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 लाख 34 हजार वोट मिले। यानी लोकसभा चुनाव के लगभग बराबर। विधानसभा में भाजपा को 1 लाख 75 हजार वोट मिले। बीजेपी के वोटों में 56 हजार की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह है कि कामठी में सिर्फ 35 हजार नए मतदाता बढ़े । बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के कामठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। इसी विधानसभा सीट का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। ◆◆◆

Courtesy : **bbc.com**

अजय कुमार द्विवेदी, कानपुर ब्यूरो प्रमुख

11 सीनियर अफसरों को पीछे छोड़ राजीव कृष्ण कार्यवाहक डीजीपी

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। 31 मई को तत्कालीन कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर हुए और इसके बाद राजीव कृष्ण को यह ज़िम्मेदारी दी गई है। पद ग्रहण करने के एक दिन बाद राजीव कृष्ण ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण और कानून व्यवस्था उनके लिए अहम काम है। 2 मई सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे, संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी कानून प्रवर्तन रणनीति की आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस हैं।राजीव कृष्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्र अफसरों मे गिने जाते हैं। संभवतः यही वजह है कि 11 सीनियर आईपीएस अफसरों को पीछे छोड़ते हुए वह डीजीपी बने हैं।

11 अफ़सरों को किया सुपरसीड

उत्तर प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि राजीव कृष्ण हालिया सिपाही भर्ती को सुचारू रूप से संपन्न कराने के कारण योगी आदित्यनाथ के खास अफसर बन गए हैं। प्रदेश में सिपाही की 60, 233 पदों पर हाल ही में भर्ती हुई है। दरअसल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी, 2024 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार की किरकिरी हुई थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया और राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, यूपी कैडर के कई अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण भी रेस से बाहर हो गए। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक और यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी की इस वक्त पाकिस्तान से तनाव के कारण राज्य में वापसी मुश्किल थी।

1989 बैच के सीनियर आईपीएस आदित्य मिश्रा रिटायर इस महीने यानी जून में रिटायर हो जाएंगे और आशीष गुप्ता ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले लिया है। मौजूदा सरकार में शफी अहसान रिजवी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष 1990 बैच की रेणुका मिश्रा प्रतीक्षारत हैं। वो मार्च 2024 से किसी पद पर नहीं हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक होने के कारण उनको डीजीपी ऑफि स से अटैच किया गया था और वो अभी भी यहीं हैं। इसके अलावा संदीप सालुंके, बीके मौर्य, तिलोत्तमा वर्मा, एमके बशाल और पीयूष आनंद भी डीजीपी की दौड़ में शामिल थे। ये सभी 1989 से 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 31 मई को रिटायर हुए प्रशांत कुमार ने भी कई ऑफिसरों को सुपरसीड किया था। जिसमें एस एन साबत, पीवी रामाशास्त्री जैसे आईपीएस अधिकारी थे। जहां तक अफसरों को सुपरसीड करने की बात है, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलाहंस का कहना है कि ये पहले की सरकारों में भी होता रहा है।

डीजीपी की नियुक्ति पर सियासत

उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति होने के बाद राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में प्रदेश की जनता पिस रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बदहाल कानून-व्यवस्था क्यों झेले? जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश-प्रदेश क्या चलाएंगे।

अफसरों का परिवार

एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए कार्यवाहक डीजीपी का परिवार सिविल सेवाओं से जुड़ा है। राजीव कृष्ण की पत्नी मीनाक्षी सिंह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में हैं और वह लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत हैं। राजीव कृष्ण के साले राजेश्वर सिंह ईडी में अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक हैं। राजेश्वर सिंह की पत्नी और राजीव कृष्ण की सरहज (साले की पत्नी) नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं। राजीव कृष्ण अपने लंबे करियर में कई ज़िलों के कप्तान रह चुके हैं। उनकी तैनाती फि रोजाबाद, इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ और बरेली में जैसे ज़िलों में रही है। इसके अलावा उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएस) में भी काम करने का अनुभव है।

अखिलेश यादव ने कार्यवाहक डीजीपी को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। राजीव कृष्ण भी कार्यवाहक हैं, इससे पहले प्रशांत कुमार भी कार्यवाहक ही थे। साल 2022 में मुकुल गोयल के हटने के बाद प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिला है। प्रशांत कुमार से पहले डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार कार्यवाहक डीजीपी भी के पद पर थे। यूपी में अस्थायी डीजीपी की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। 13 मई 2022 को तत्कालीन डीजी इंटेलिजेंस देवेंद्र सिंह (डीएस) चौहान को नियुक्त किया गया था। उनके 31 मार्च 2023 को रिटायर होने के बाद आरके विश्वकर्मा सिर्फ. दो महीने के लिए उस पद पर रहे। आरके विश्वकर्मा के तुरंत बाद विजय कुमार इस पद पर नियुक्त हुए, फिर 31 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी बने रहे। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलाहंस का कहना है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य की कमी हो तो इस तरह के निर्णय होते हैं। सिद्धार्थ कलाहंस कहते हैं कि अगर यूपीएससी के जरिए नियुक्ति होती है तो उसमें वरिष्ठता के आधार पर नाम भेजना होता है, इसमें राज्य की सरकार अपने चहेते अफसर को नियुक्त नहीं कर पाती है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी नए डीजीपी को लेकर कहा है कि उनके सामने कई चुनौतियां है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं साम्प्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय-अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से यह साबित है कि यहां कानून का राज सही से नहीं चल रहा है ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण व कानून का राज स्थापित करके सर्वसमाज के लोगों को उचित राहत पहुँचाने का बड़ा चैलेंज है, राज्य सरकार व सत्ताधारी दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर प्रकार का सहयोग व सक्रियता जरूरी है। जब राजीव कृष्ण से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के बयान पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। डीजीपी ने कहा कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हालांकि, अलीगढ़ में पिछले हफ्ते ही चार लोगों को गोमांस ले जाने के शक में भीड़ ने पीटा था। जबकि उनके पास भैंस का मांस ले जाने के वैध दस्तावेज थे। बाद में लैब टेस्ट में भी मांस भैस का मांस निकला। इस बर्बर मारपीट के बारे में जब बीबीसी ने सवाल किया तो डीजीपी ने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशांत कुमार को नहीं मिला सेवा विस्तार

प्रशांत कुमार को आखिरी वक्त पर सेवा विस्तार नहीं मिला है। इस वजह से राज्य सरकार को नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करना पड़ा। रिटायर होने के बाद प्रशांत कुमार ने पुलिस महकमे के लोगों का धन्यवाद किया है। एक्स पर प्रशांत कुमार ने लिखा कि वर्दी में पहले दिन से लेकर इस मौके. तक, मैं हर दिन लोगों की सेवा करने, न्याय को बनाए रखने और अपनी पुलिस के साथ खड़ा रहा हूँ । उन्होंने कहा कि वर्दी अस्थायी है लेकिन ड्यूटी हमेशा के लिए है। हालांकि, अखिलेश यादव ने प्रशांत कुमार के बारे में कहा कि आज जाते-जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम-से-कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते।

यूपी सरकार ने बनाई थी गीइडलाइन

नवंबर, 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए पुलिस महानिदेशक के चयन की नई प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत डीजीपी के चयन के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव था। ये समिति हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में नए डीजीपी का चयन करने के लिए प्रस्तावित थी। इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य, राज्य सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी, राज्य के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव और राज्य के पूर्व डीजीपी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। हालांकि, अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। इसको लेकर पूर्व अधिकारियों की राय अलग-अलग थी। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बीबीसी से उस वक्त कहा कि पहले की प्रक्रिया ज्यादा फेयर थी। नई प्रकिया पूरी तरह से सरकार के अधीन होगी। समिति में मौजूद यूपीएससी के सिर्फ. एक सदस्य की राय की ज्यादा अहमियत नहीं होगी। सरकार मनमाने ढंग से नियुक्ति भी करेगी और हटाएगी भी। प्रशासन का लंबा अनुभव रखने वाले आलोक रंजन के मुताबिक, जूनियर अधिकारियों के प्रमोट होने से उन सीनियर अफसरों का मनोबल गिरेगा, जिन्होंने 30 से 35 साल सेवा में दिए हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार में मुख्य सचिव और डीजीपी के दो पद ऐसे हैं, जिन्हें राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए। राज्य के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा था कि ये गाइडलाइन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की मंशा के खिलाफ है। हालांकि, पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता बृज लाल का कहना था कि डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली सही है और इस निर्णय के आने वाले समय में अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। ◆◆◆

रानू पाठक, राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

राजस्थान की डिप्टी सीएम का हल्दीघाटी पर दिए गए बयान पर छिड़ा विवाद

हल्दीघाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बयान से एक बार फिर विवाद छिड़ गया है।जयपुर में एक कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा, ह्लहल्दीघाटी के शिलालेख में लिखा था कि महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। मैं उस समय वहां से सांसद थी, मैंने उस शिलालेख को बदलवाया। और आज वहां लिखा है कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। अपने कार्यकाल में यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।ह्वदिया कुमारी ने इसके लिए राजस्थान से ही आने वाले तत्कालीन संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल के सहयोग का ज़िक्र किया, जिन्होंने पूर्व लिखित शिलापट्ट हटाने का आदेश दिया था।असल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने 2021 में राजस्थान के राजसमंद ज़िले के रक्ततलाई से वो विवादित शिलालेख हटा दिया था, जिस पर लिखा था कि 1576 में हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने एक्स पर लिखा, ह्लआपके पूर्वज राजा मानसिंह ने हकीम खान सूर के खिलाफ हल्दीघाटी जीता था। एक राजपूत सेनापति ने एक मुस्लिम सेनापति को हराया। आप इतिहास को फिर से क्यों लिखना चाहती हैं?ह्वबहुचर्चित हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की ओर से सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप की ओर से सेनापति हकीम खान सूर लड़ रहे थे।इसी साल अप्रैल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हकीम खान सूर हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे।

शिलापट्ट पर क्या लिखा था?

रक्ततलाई का जो शिलापट्ट हटाया गया है, उस पर लिखा था, ''रक्ततलाई जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं, बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप एवं मानसिंह घोड़े और हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून, 1576 को समाप्त हो गया।''इस शिलालेख को हटाने की तब दिया कुमारी ने मांग की थी।इसे हटाते हुए जोधपुर के तत्कालीन एएसआई सर्कल सुपरिटेंडेंट बिपिन चंद्र नेगी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, ''1975 में जब इंदिरा गाँधी इन इलाकों में आई थीं तब चेतक समाधि, बादशाह बाग, रक्ततलाई और हल्दीघाटी में ये पट्टियाँ लगाई गई थीं। उस वक्त ये स्मारक केंद्र की देखरेख में नहीं आते थे। इन स्थानों को 2003 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, लेकिन इन शिलापट्टों पर ये सूचनाएँ नहीं थीं। लंबे समय के कारण ये पुराने पड़ गए थे। इसके साथ ही तारीख और तथ्य को लेकर विवाद भी थे।''उन्होंने कहा था, ''इतिहास के जानकारों और जनता के प्रतिनिधियों से इन शिलालेखों को हटाने के लिए कई अनुरोध आये थे। इन्हीं को देखते हुए, मैंने स्वतः संज्ञान लिया।ह्व

आठ साल पहले हुआ था पाठ्यक्रम में बदलाव

साल 2017 में राजस्थान बोर्ड की किताबों के पाठ्यक्रम में हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में तथ्य बदल दिए गए थे जिसे लेकर विवाद हुआ था।उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोशल साइंस की नई किताब को 2017-18 में छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था।किताब के इस चैप्टर को लिखने वाले चंद्रशेखर शर्मा ने दावा किया था कि 'ऐसे कई तथ्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि लड़ाई के नतीजे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजपूत राजा के पक्ष में रहे।'तब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन बीएल चौधरी ने बीबीसी को बताया था कि किताब में कहीं भी सीधे-सीधे यह नहीं लिखा गया है कि युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया।उन्होंने कहा था, ह्लकुछ इतिहासकारों ने इसे परिणामविहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। परिणाम की समीक्षा के लिए कुछ बिंदु विचारणीय हैं। अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को ज़िंदा पकड़ना

था और दूसरे वो मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था और दोनों ही उद्देश्यों में वो विफल रहा। इससे साबित होता है कि अकबर की विजय नहीं होती है। अकबर की मानसिंह और आसिफ खां के प्रति नाराजगी थी जिसमें उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी। मुगलों का मेवाड़ की सेना का पीछा न करना। ये ऐसे बिंदु हैं जो हल्दीघाटी का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। तब सोशल मीडिया पर यह खबर चर्चित हुई थी और कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा था कि '450 साल बाद आखिरकार महाराणा प्रताप ने अकबर को धूल चटा दी।'

हल्दीघाटी की लड़ाई

अब्दुल कादिर बदायूंनी की 'मनतखब-उत-तवारीख', निजामुद्दीन की 'तबाकत-ए-अकबरी' और अबुल फजल की 'अकबरनामा' जैसी इतिहास की किताबों में हल्दीघाटी के युद्ध का विस्तृत विवरण है। इतिहासकारों के अनुसार, हल्दीघाटी की लड़ाई 21 जून, 1576 को हुई थी। मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह।शुरू में ऐसा लग रहा था कि राजपूत, मुगलों पर भारी पड़ रहे हैं लेकिन अकबर के खुद युद्ध में शामिल होने की अफवाह से राजपूतों का मनोबल टूट गया।इस लड़ाई में मेवाड़ की फौज का मुख्य हाथी राम प्रसाद का महावत मारा गया।'महाराणा प्रताप- द इनविंसिबिल वारियर' की लेखिका रीमा हूजा के अनुसार, ह्लइस युद्ध में महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और मानसिंह के हाथी की सूंढ़ में लगी तलवार से प्रताप का घोड़ा चेतक बुरी तरह घायल हो गया।ह्लह्लमेवाड़ की फौज के जनरलों ने तय किया कि पीछे हट जाना चाहिए और महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाना चाहिए। यह लड़ाई उसी दिन समाप्त हो गई थी।ह्ल

क्यों है विवाद

हल्दीघाटी की लड़ाई को मुगलों की स्पष्ट जीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अबुल फजल समेत उस समय के कई इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर इस लड़ाई के परिणाम से बहुत खुश नहीं थे।उनका कहना है कि उन्होंने बहुत समय तक इस लड़ाई के जनरलों मान सिंह, आसफ खाँ और काजी खाँ को अपने दरबार में पेश होने की इजाजत नहीं दी।हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप अकबर की सेना के खिलाफ छापामार युद्ध करने लगे। वो मुगलों पर घात लगाकर हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। करीब दो दशक तक वह इसी तरह युद्ध लड़ते रहे। 1596 में शिकार खेलते वक़्त वह घायल हो गए थे और इसके दो साल बात ही 57 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया।लेकिन कई दक्षिणपंथी इतिहासकारों का मानना है कि अकबर को महाराणा प्रताप और मेवाड़ पर कभी मुकम्मल जीत नहीं मिली और इसलिए हल्दीघाटी के युद्ध के परिणाम प्रताप के पक्ष में ला खड़ा करते हैं।वहीं डॉ। राम पुनियानी जैसे इतिहासकार इसे दो राजाओं के बीच युद्ध बताते हैं। राम पुनियानी के अनुसार, इसे हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई बताई जाती है।◆◆◆

'कलम और कवच 2.0'

रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यू आईडीएस) के तत्वावधान में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र (सीईएनजेओडब्ल्यूएस) ने पेंटागन प्रेस के सहयोग से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा साहित्य महोत्सव 'कलम और कवच 2.0' का दूसरी बार सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस वर्ष का विषय 'रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना' था। 15 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से भविष्य के युद्ध पर रक्षा विनिर्माण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, रणनीतिक नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। चर्चाओं में प्रौद्योगिकी और भविष्य के युद्ध, आधुनिक सैन्य अभियानों में आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स, साइबर प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अर्धचालकों की भूमिका, रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता, अधिग्रहण और खरीद सुधार सहित कई अत्याधुनिक विषय शामिल थे।

असमिया नववर्ष 'रोंगालीर एनजोरी'

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में अपने आधिकारिक निवास पर रोंगाली बिहू और असमिया नववर्ष के उपलक्ष्य में जीवंत उत्सव 'रोंगालीर एनजोरी' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले असमिया और पूर्वोत्तर समुदायों के कई गणमान्य व्यक्ति, कलाकार और सदस्य भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, 'रोंगाली बिहू हम सभी के लिए राष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आता है। यह त्योहार सिर्फ उत्सव मनाने के बारे में ही नहीं है- वरन यह एकता, परंपरा और हमारी साझा सांस्कृतिक पहचान के बारे में है।' प्रसिद्ध असमिया गायकों निलुत्पल बोरा, सुरेखा छेत्री और जुटिमला बुरागोहैन ने संगीतमय प्रस्तुति दी। उन्होंने पारंपरिक धुनों और लय से दर्शकों का मन मोह लिया।

पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत पर कथाएँ (2014-2025) और कथित पक्षपात

विकास पारिक...
लंदन से

परिचय

2014 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब से प्रमुख पश्चिमी मीडिया संस्थान झ जैसे बीबीसी, स्काई न्यूज, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स झ ने अक्सर भारत को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है।

इनकी रिपोर्टिंग का ध्यान कश्मीर, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), किसानों के विरोध, भारत की विदेश नीति, मानवाधिकार और लोकतंत्र में कथित गिरावट जैसे विवादास्पद मुद्दों पर केंद्रित रहा है। भारतीय अधिकारी और विश्लेषक बार-बार इन मीडिया संस्थानों पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि ये संस्थान एकतरफा कथाएँ पेश करते हैं जो या तो संदर्भ की अनदेखी करते हैं या भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि ये रिपोर्टिंग एक व्यापक भू-राजनीतिक एजेंडे से जुड़ी होती है जिसे 'डीप स्टेट' दृष्टिकोण कहा जाता है जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुँचाना है। नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें प्रत्येक संस्थान से कुछ प्रमुख लेखों का उल्लेख है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कथित पक्षपात की प्रकृति को दर्शाती है:

केस स्टडी 1: कश्मीर आतंकवाद बनाम मानवाधिकार

2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर पर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग का मुख्य जोर सुरक्षा बंदी, संचार कटौती और मानवाधिकार हनन पर रहा।

बीबीसी ने ऐसे पीड़ितों की कहानियाँ दिखाई जिन्होंने दावा किया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें पीटा, गोली मारी या प्रताड़ित किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने मुझे गोली मारी और मैं जमीन पर गिर गया शीर्षक वाली रिपोर्ट को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दी: हिंदू-नेतृत्व वाली भारत सरकार मुस्लिम कश्मीर पर शिकंजा कस रही है, जिसमें भारत की कार्रवाई को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा गया। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि 3,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे। उन्होंने आयरन हैंड यानी लोहे की छड़ी से शासित सामान्य स्थिति का उल्लेख किया। भारतीय अधिकारियों ने इन सभी रिपोर्टों को एकतरफा और संदर्भ से कटी हुई बताया है। रक्षा विशेषज्ञों और संपादकों ने आरोप लगाया कि बीबीसी जैसे चैनल जानबूझकर वीडियो को संपादित कर के झूठा माहौल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, बीबीसी के एक वीडियो में गोलीबारी की आवाजें जोड़ी गईं जो कि असली नहीं थीं यह बात भारतीय पत्रकारों और अधिकारियों ने उजागर की।

सरकार का कहना है कि पश्चिमी मीडिया आर्तकियों को आतंकवादी कहने के बजाय उग्रवादी या बंदूकधारी जैसे नरम शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे उनके कृत्यों की गंभीरता कम हो जाती है। 2025 में पहलगाम में हुए आत्मघाती हमले में 26 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे, फिर भी बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमलावरों को मिलिटेंट्स कहा, टेररिस्ट नहीं। इस भाषा चयन को लेकर न केवल भारत में बल्कि अमेरिकी कांग्रेस में भी आलोचना हुई। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी ने ट्वीट कर न्यूयॉर्क टाइम्स की भाषा की आलोचना की और इसे वास्तविकता से दूर बताया। भारतीय विश्लेषकों ने इसे टेरर वॉशिंग कहा झ यानी आतंक को नरम शब्दों में लपेटना। साथ ही यह भी कहा गया कि जब पीड़ित हिंदू होते हैं, तो उनकी पहचान छुपाई जाती है।

सरकारी विभागों ने इन रिपोर्टों का खंडन करने के लिए बार-बार बयान जारी किए। उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि कश्मीर में दवाइयाँ नहीं मिल रही थीं, जिसे भारत सरकार ने आँकड़ों सहित खारिज किया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह स्थिति बढ़ा-चढ़ा कर पेश की जाती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब कश्मीरी हिंदुओं को 1990 के दशक में आतंकियों ने मारकर भगा दिया, तब पश्चिमी मीडिया ने एक शब्द भी नहीं कहा।

मीडिया संस्थान	लेख (विषय)	तारीख	प्रस्तुति और कथित पक्षपात की प्रकृति
बीबीसी	"कश्मीर अशांति: 'उन्होंने मुझे गोली मारी और मैं ज़मीन पर गिर गया'" (कश्मीर)	अगस्त 2019 (अनुच्छेद 370 हटाने के बाद)	कथित रूप से सेना द्वारा किए गए अत्याचारों पर केंद्रित; पीड़ितों की अपुष्ट कहानियों पर निर्भरता, जिसे भारतीय सेना ने खारिज किया।
स्काई न्यूज़	"भारत में किसानों का विरोध: मोदी पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं" (कृषि कानून)	दिसंबर 2020	कानूनों को "विवादास्पद" कह कर जनता के गुस्से को उभारने वाली रिपोर्टिंग; सरकार के पक्ष की संक्षिप्त झलक मात्र।
वाशिंगटन पोस्ट	"भारत में विरोध एक सत्तावादी सरकार के खिलाफ निर्णायक मोड़ हो सकता है" (CAA/NRC)	दिसंबर 2019	सरकार को अधिनायकवादी बताते हुए मुस्लिम विरोधी एजेंडा पर ज़ोर; फासीवाद के आरोपों तक का ज़िक्र।
न्यूयॉर्क टाइम्स	"हिंदू-नेतृत्व वाली भारत सरकार मुस्लिम कश्मीर पर शिकंजा कस रही है" (कश्मीर)	अगस्त 2019	अनुच्छेद 370 हटाने को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखने का प्रयास; पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की अनदेखी।

इससे यह संकेत मिलता है कि पश्चिमी मीडिया की सहानुभूति पक्षपाती है यानी मानवाधिकार की चिंता तब ही होती है जब वह एक खास नैरेटिव को सूट करती हो।

इन रिपोर्टों में अक्सर यह भी नहीं बताया गया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, लगातार हुए हमले, और सेना की कार्रवाई का औचित्य क्या था।

निष्कर्षतः, भारत सरकार और समर्थक विश्लेषक मानते हैं कि कश्मीर पर पश्चिमी मीडिया की कवरेज पूर्वनिर्धारित नैरेटिव के अनुसार होती है झ जहां भारत हमेशा आक्रामक, दमनकारी और मुस्लिम विरोधी दिखाया जाता है।

केस स्टडी 2: उअअझ्रठफ्ठ झ्र धर्मनिरपेक्षता बनाम मुस्लिम विरोधी पूर्वग्रह

2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (उअअ) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (ठफ्ठ) पर पश्चिमी मीडिया की कवरेज मुख्यतः आलोचनात्मक रही। उअअ, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की सुविधा देता है, को बार-बार मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में चित्रित किया गया।

वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि उअअ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और ह्लमुसलमानों को विशेष रूप से बाहर रखता हैह्व। उन्होंने इसे भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव से विचलन के रूप में पेश किया। न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन जैसे प्रकाशनों ने देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को प्रमुखता दी। इन रिपोर्टों ने उअअ को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या फैसले जैसे अन्य मुद्दों के साथ जोड़कर एक व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा के रूप में प्रस्तुत किया। वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि भारत अपने ही आप से युद्ध में है और यह विरोध सत्तावाद के विरुद्ध एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। लेख में मुस्लिम विश्वविद्यालयों में पुलिस कार्यवाही की आलोचना की गई और प्रधानमंत्री मोदी पर ह्लनफरत भरी टिप्पणियोंह्व के आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि कुछ लेखों में विदेशों के राजनयिकों के हवाले से यह तक कहा गया कि वे भारत में फासीवाद के आरोपों की जांच कर रहे हैं। यानी पूरी मीडिया कथा यह बना रही थी कि भारत में अल्पसंख्यकों का दमन और लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है।

भारतीय पक्ष पूर्वग्रह-गलत सूचना का आरोप

भारत सरकार ने इन रिपोर्टों को भ्रामक, 'जानबूझकर एकतरफा और राजनीतिक रूप से प्रेरित' करार दिया। उन्होंने बार-बार स्पष्ट किया कि उअअ किसी की नागरिकता नहीं छीनता, बल्कि केवल पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरण देता है। सरकारी प्रवक्ताओं ने कहा कि ठफ्ठ अभी केवल प्रस्तावित है और उसका उअअ से कोई सीधा संबंध नहीं है।

CAA के आलोचकों पर सरकार समर्थक विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि वे मुसलमानों के नाम पर झूठा भय फैला रहे हैं और पश्चिमी मीडिया ने बिना तथ्य जांचे इस नैरेटिव को अपना लिया।

एक मुखर विश्लेषक ने इसे 'पाखंड और छद्म धर्मनिरपेक्षता का अभियान बताया, जो केवल इसीलिए पनपा क्योंकि मोदी सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी माना जाता है और पश्चिमी मीडिया पहले से ही उस पर अविश्वास करता है। उनका कहना है कि पश्चिमी मीडिया का दृष्टिकोण पहले से ही इस पूर्वग्रह से ग्रस्त था कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, इसलिए किसी भी कानून को उसी चश्मे से देखा गया।

विरोध प्रदर्शन और दोहरे मानदंड

उअअ के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को पश्चिमी मीडिया ने ह्लस्वतंत्रता के लिए संघर्षह्व के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि जब यह प्रदर्शन हिंसक हुए (जैसे कि दिल्ली दंगे), तब प्रदर्शनकारियों की हिंसा को नजरअंदाज किया गया और केवल पुलिस कार्रवाई को ह्लबर्बरताह्व बताया गया।

सरकार का कहना था कि दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई झड़पों में पुलिस ने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले किया था। पश्चिमी मीडिया में, प्रदर्शनकारियों को शांतिप्रिय, संविधानवादी बताकर महिमामंडित किया गया, जबकि हिंसक तत्वों की भूमिका को या तो छिपाया गया या कम करके बताया गया। इससे भारतीय सरकार और उसके समर्थकों में यह धारणा बनी कि यह सब एक सोची-समझी अंतरराष्ट्रीय छवि बिगाड़ने की रणनीति का हिस्सा है। सरकारी प्रवक्ताओं ने पश्चिमी देशों की पाखंडी नीति की ओर इशारा किया झ जैसे फ्रांस में हिंसक प्रदर्शनों पर कठोर दमन को उचित ठहराना, लेकिन भारत में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को 'मानवाधिकार उल्लंघन' बताना।

निष्कर्ष

लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग झ चाहे वह उअअ हो, कश्मीर हो, पत्रकारों की गिरफ्तारी हो, या सांस्कृतिक सेंसरशिप बार-बार भारत को एक बिगड़ता हुआ लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्रवाद के चंगुल में फंसा देशह्व के रूप में चित्रित करती है।

भारतीय दृष्टिकोण से यह एक पूर्वनिर्धारित नैरेटिव है, जो वास्तविकता की कई परतों को नजरअंदाज करता है झ जैसेः

भारत में नियमित चुनाव होते हैं

अदालतें सरकार के खिलाफ फैसले देती हैं

मीडिया में कई स्वर स्वतंत्रता से बोलते हैं

भारत की विविधता और धार्मिक सहिष्णुता अभी भी कायम है

भारत के नीति निर्धारक इसे नव-औपनिवेशिक दबाव तंत्र मानते हैं झ जहाँ पश्चिम चाहता है कि भारत उनके लोकतांत्रिक मापदंडों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और रणनीतिक दिशा के अनुरूप चले। जब भारत इससे अलग चलता है, तो मीडिया की आलोचना तेज हो जाती है।

अंतिम टिप्पणी

आलोचना हमेशा नकारात्मक नहीं होती, लेकिन जब रिपोर्टिंग बार-बार पूर्वग्रह, चयनात्मकता, और स्टीरियोटाइप्स से ग्रस्त हो, तो वह पत्रकारिता नहीं रह जाती झ वह एक राजनीतिक औजार बन जाती है।

भारत को अपने आत्मविश्वास, तथ्यों और विश्व मंच पर अपनी आवाज के जरिए इस नैरेटिव को चुनौती देनी होगी। यह लड़ाई केवल छवि की नहीं, बल्कि वैचारिक स्वाधीनता और राष्ट्रीय सम्मान की है। ◆◆◆

गढ़वाली सिनेमा की नयी उड़ान

'द्वि होला जब साथ ने' मचाई धूम

मई के पहले सप्ताह में मुझे इंदिरापुरम, एनसीआर गाजियाबाद स्थित जयपुरिया मॉल में एक गढ़वाली फिल्म द्वी होला जब साथद्व देखने का मौका मिला। हालांकि शुरू में गढ़वाली फिल्म के शीर्षक ने मुझे आश्वस्त नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि फिल्म शायद बहुत सफल नहीं होगी। लेकिन चूंकि मुझे फिल्म के एक अभिनेता, एक अनुभवी कलाकार विमल उनियाल और मेरे एक करीबी दोस्त ने आमंत्रित किया था, इसलिए मेरे पास न चाहते हुए भी रोहिणी से जयपुरिया मॉल तक की यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि इन दिनों क्षेत्रीय उत्तराखंडी फिल्में तेजी से बन रही हैं, खासकर उत्तराखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय फिल्मों पर पचास प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा के बाद, फिल्मों की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।

लेकिन इसके बावजूद यह जरूर मानना होगा कि धीरे-धीरे गढ़वाली कुमाऊंनी फिल्मों में काफी सुधार हुआ है और अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने की जरूरत है जो वास्तव में नहीं हो रहा है।

थिएटरों में आम तौर पर पचास प्रतिशत से भी कम क्षमता होती है, हालांकि सोशल मीडिया और स्थानीय प्रिंट मीडिया में भी इन फिल्मों को लेकर खूब चर्चा हो रही है।

हालांकि, इन सबके बावजूद झ कई खूबसूरत, निपुणता और कुशलता से निर्मित फिल्में निश्चित रूप से सामने आ रही हैं झ इनमें से कुछ के नाम हैं सेबहेरू गम, बथौन, मेजर निराला, मेरू गांव, असगर, अनुभवी निर्देशक अनुज जोशी द्वारा निर्देशित कई फिल्में और जब द्वी होला साथ, कारा, आदि आदि।

वैसे तो उत्तराखंडी फिल्मों के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कई कमियों के बावजूद अच्छे निर्देशक, निमार्ता और अभिनेता, पटकथा

लेखक उत्तराखंड में खूबसूरत और मनमोहक लोकेशन पर अच्छी फिल्में बनाने के लिए आ रहे हैं। अगर हम पिछले पांच-दस सालों में फिल्म निर्माण की दर देखें तो अच्छी संख्या में फिल्में एक साल में ही सिनेमाघरों में देखने के लिए तैयार हो जाती हैं और कभी-कभी तो एक साल से भी कम समय में। हालांकि इससे उत्तराखंडी फिल्मों की स्थिति का अच्छा और उत्साहवर्धक चित्र मिलता है, लेकिन तेजी से फिल्म निर्माण में फिल्मों की गुणवत्ता और निर्माण बुरी तरह प्रभावित होता है, जिससे फिल्मों के सिनेमाघरों में उचित समय तक नहीं चलने की स्थिति में उनकी गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी में फिल्में बनाने की बजाय अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फिल्में बनाने की जरूरत है। गुणवत्ता के लिए समय, सहनशीलता, अच्छे और मनोरम लोकेशन, शानदार पटकथा, बेहतर संवाद अदायगी, बेहतरीन

पार्श्व संगीत, मधुर अर्थपूर्ण गीत और सबसे बढ़कर बेहतरीन आवाज और अभिनय प्रतिभा वाली सुंदर और खूबसूरत अभिनेत्रियों की जरूरत होती है, ताकि दर्शकों की गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय फिल्मों के प्रति इच्छा और भूख पूरी हो सके। कल इंदिरापुरम के जयपुरिया मॉल में गढ़वाली फिल्म ह्वद्वी होला जब साथह्व के प्रीमियर पर ऐसा लगा कि फिल्म ने दर्शकों के साथ पूरा न्याय किया है। मेरी राय में यह बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी, संवाद अदायगी, सुंदर लोकेशन और बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ मधुर गीतों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत के साथ एक शानदार फिल्म थी। निर्देशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ कमियाँ थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। फिल्म के बारे में दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक, निमार्ता और पटकथा लेखक पंजाब के एक पेशेवर कलाकार रवि दीप हैं, जिन्होंने संतोषजनक परिणाम के साथ एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए रचनात्मक रूप से सब कुछ बुना है। फिल्म दर्शकों को 2.5 घंटे तक अपनी सीटों से बांधे रखती है और कुछ तो फिल्म के अंत में आंसू भी बहाते हैं। गढ़वाली फिल्म के स्टार कास्ट, जिसे पिक्चर हॉल में आने में लगभग तीन साल लगे, ने अपनी शानदार पटकथा और निर्देशन से एक खास पहचान बनाई है, मनीष डिमरी, कल्याणी गंगोला, अमित भट्ट, अंकिता परिहार, रिया शर्मा, रमेश रावत, विमल उनियाल, सुषमा व्यास, रोशन उपाध्याय, बाल कलाकार आरव बिजलवान हैं। फिल्म का संगीत अमित वी. कपूर और बी. कैश ने दिया है, सिनेमैटोग्राफी नीलेश बाबू ने की है और संपादन दिव्या दीप महाजन ने किया है। कहानी और फिल्म के गढ़वाली रूपांतरण का श्रेय शोभना रावत को जाता है, जबकि फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर अमित दीक्षित हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों नायक, सहायक नायक, नायिका और सहायक नायिका सहित उनके माता-पिता और बाकी कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय और संवाद अदायगी से दर्शकों के साथ न्याय किया है। संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाला था और उत्तराखंड के खूबसूरत स्थानों पर गायकों की मधुर आवाज भी। फिल्म की मुख्य शूटिंग उत्तराखंड के टिहरी के स्वाखाल में रौतों की घाटी के खूबसूरत स्थानों पर की गई है। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

आयकर अधिकारी के रूप में अजय देवगन एक बार फिर से बड़े परदे पर कालाधन पकड़ने निकले हैं। सात वर्ष पूर्व आई उनकी फिल्म 'रेड' का सिक्वल 'रेड-2' दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है।

काले धन पर फिर से 'रेड'

20 18 में आई फिल्म 'रेड' के अमय पटनायक (अजय देवगन) और ताऊजी (सौरभ शुक्ला) का आमना-सामना दर्शक भूले नहीं होंगे? अब 1 मई 2025 को 'रेड-2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी है। आयकर अधिकारी अमय पटनायक एक बार फिर पर्दे पर काला धन बाहर निकालने और काला धन बनाने वालों को जेल भेजने के लिए आ गए हैं। इस बार अमय पटनायक का सामना भोज के मनोहर धनखड़ उर्फ दादा भाई (रितेश देशमुख) से होता है। दादा भाई भोज की जनता के लिए देवता पुरुष है।

फिल्म की शुरुआत में अमय पटनायक रात के समय राजा साहब (गोविंद नामदेव) के यहां रेड मारता है। इस रेड में राजा साहब अपना काला धन छुपाने का भरसक प्रयास करते हैं लेकिन उनका काला धन पकड़ा जाता है। उसके बाद ही अखबार में खबर छपती है कि 'अमय पटनायक ने दो करोड़ की घूस ली'। इस खबर के बाद अमय पटनायक का 74वां ट्रांसफर भोज में कर दिया जाता है। यहां वह अपनी पत्नी मालिनी (वाणी कपूर) और बेटी मिनी के साथ जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि दादा भाई एक फाउंडेशन चलाते हैं, जिससे वह लोगों की बहुत मदद करते हैं। वह अपनी माता (सुप्रिया पाठक) का पैर धोकर उनकी अर्चना करके दिन की शुरुआत करते हैं। पटनायक को शक होता है कि भोज में इतना सब कुछ ठीक कैसे हैं? और वह छानबीन शुरू कर देता है।

अमय पटनायक की छानबीन में दादा भाई का सारा काला चिट्ठा उसके सामने आ जाता है। वह कैसे सोने की काला बाजारी करता है और अवैध जमीनों का भंडार लेकर बैठा है। यही नहीं उसने बहुत सी लड़कियों का शोषण भी किया है। इन बातों का पता चलने पर पटनायक अपनी टीम के साथ दादा भाई के घर रेड करने पहुंच जाता है। लेकिन दादा भाई के घर पर अमय पटनायक को कोई काला धन नहीं मिलता है। उसके हाथ लगती है, निराशा और सस्पेंशन लेटर। और यहीं से शुरू होती है अमय पटनायक और दादा भाई की शतरंज वाली शह और मात का खेल। अब फिल्म में आगे यही देखना है कि अमय पटनायक कैसे दादा भाई के काले धन को पकड़ता है और अपना सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल कराता है। भोज की जनता जिस दादा भाई को देवता पुरुष समझती है, उसकी असलियत को जनता के सामने कैसे लाता है? फिल्म का सस्पेंस अंत में खुलता है। यदि फिल्म में अभिनय की बात करें तो अजय देवगन एक आयकर अधिकारी के स्वैग और एटीट्यूड में बहुत जचे हैं। रितेश देशमुख ने विलेन के किरदार में पहले भी लोगों का दिल जीता है और इस बार भी उनका अभिनय शानदार रहा है। वाणी कपूर (मालिनी) एक सपोर्टिंग और समझदार पत्नी के रूप में नजर आई है। लल्लन सुधीर के किरदार अमित सियाल में अपने अभिनय से हंसाते और दर्शकों का दिल जीतने कामयाब हुए हैं। फिल्म का गाना 'तुम्हें दिल्लगी...' नए वर्जन में जुबिन नौटियाल की आवाज में काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म का आइटम सॉन्ग 'नशा...' इस समय ट्रेंडिंग में हैं। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवन

केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने पारंपरिक चिकित्सा में देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दो दुर्लभ और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक पांडुलिपियों - द्रव्यरत्नाकरनिघण्टुः और द्रव्यनामाकरनिघण्टुः को पुनर्जीवित किया है। इन प्रकाशनों का अनावरण मुंबई में राजा रामदेव आनंदीलाल पोदार (आरआरएपी) केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक वैद्य रविनारायण आचार्य उपस्थित थे। उन्होंने पारंपरिक आयुर्वेदिक साहित्य के अनुसंधान, डिजिटलीकरण और पुनरुद्धार में 'केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय की गतिविधियों' पर मुख्य भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं- वे जीवित ज्ञान प्रणालियां हैं जो सोच-समझकर अध्ययन और लागू किए जाने पर समकालीन स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। मुंबई के प्रसिद्ध पांडुलिपिविज्ञानी और अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञ, डॉ. सदानंद डी. कामत द्वारा पांडुलिपियों का आलोचनात्मक संपादन और अनुवाद किया गया था।

आईपीएल 2025 फाइनल

आरसीबी ने आईपीएल खिताब किया अपने नाम

आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार खिताब को अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में टॉस हारने के बाद आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 184 रन ही बना सकी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि यह मेरे लिए, विराट कोहली के लिए और सभी प्रशंसकों के लिए बहुत खास है। जिन्होंने सालों से समर्थन किया है, वे सभी इसके हकदार हैं। क्वालिफायर के बाद, हमने सोचा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस ट्रैक पर 190 एक अच्छा स्कोर था क्योंकि यह थोड़ा धीमा था। गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को जिस तरह से अंजाम दिया, वह देखने लायक था। क्रुणाल एक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जब भी हमें विकेट की जरूरत होती है तो मैं उन्हें देखता हूं। सुयश और तेज गेंदबाज पूरे सीजन में अच्छे थे। शेफर्ड ने आज रात महत्वपूर्ण विकेट लिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और कोहली की कप्तानी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, वह किसी और से ज्यादा इसके हकदार हैं। मैं सभी प्रशंसकों से सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं - ई साला कप नमदु। रजत पाटीदार का कहना है कि यह जीत उनके लिए, विराट कोहली और सभी प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखती है। उनका मानना है कि सालों से टीम का समर्थन करने वाले सभी लोग इस जीत के हकदार हैं। क्वालिफायर मैच के बाद उन्हें लगा कि वे फाइनल तक जा सकते हैं। पाटीदार के अनुसार, पिच थोड़ी धीमी थी, इसलिए 190 रन का स्कोर अच्छा था। उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी योजनाओं को बहुत अच्छी तरह से लागू किया। पाटीदार ने क्रुणाल पांड्या को विकेट लेने वाला गेंदबाज बताया और कहा कि जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है, तो वे उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। उन्होंने सुयश और टीम के तेज गेंदबाजों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। पाटीदार ने शेफर्ड द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण विकेट का भी उल्लेख किया। रजत पाटीदार ने विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी की कप्तानी करने को अपने लिए एक बड़ा अवसर और सीखने का अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली किसी और से ज्यादा कप्तानी के हकदार हैं। अंत में, उन्होंने सभी प्रशंसकों से ई साला कप नमदु कहा, जिसका अर्थ है यह कप हमारा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ रुपये का विजेताओं का चेक मिलता है। इस सीजन में कप्तान नियुक्त किए गए रजत पाटीदार, आरसीबी की ओर से इसे लेते हैं। ◆◆◆

प्रस्तुति : **प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क**

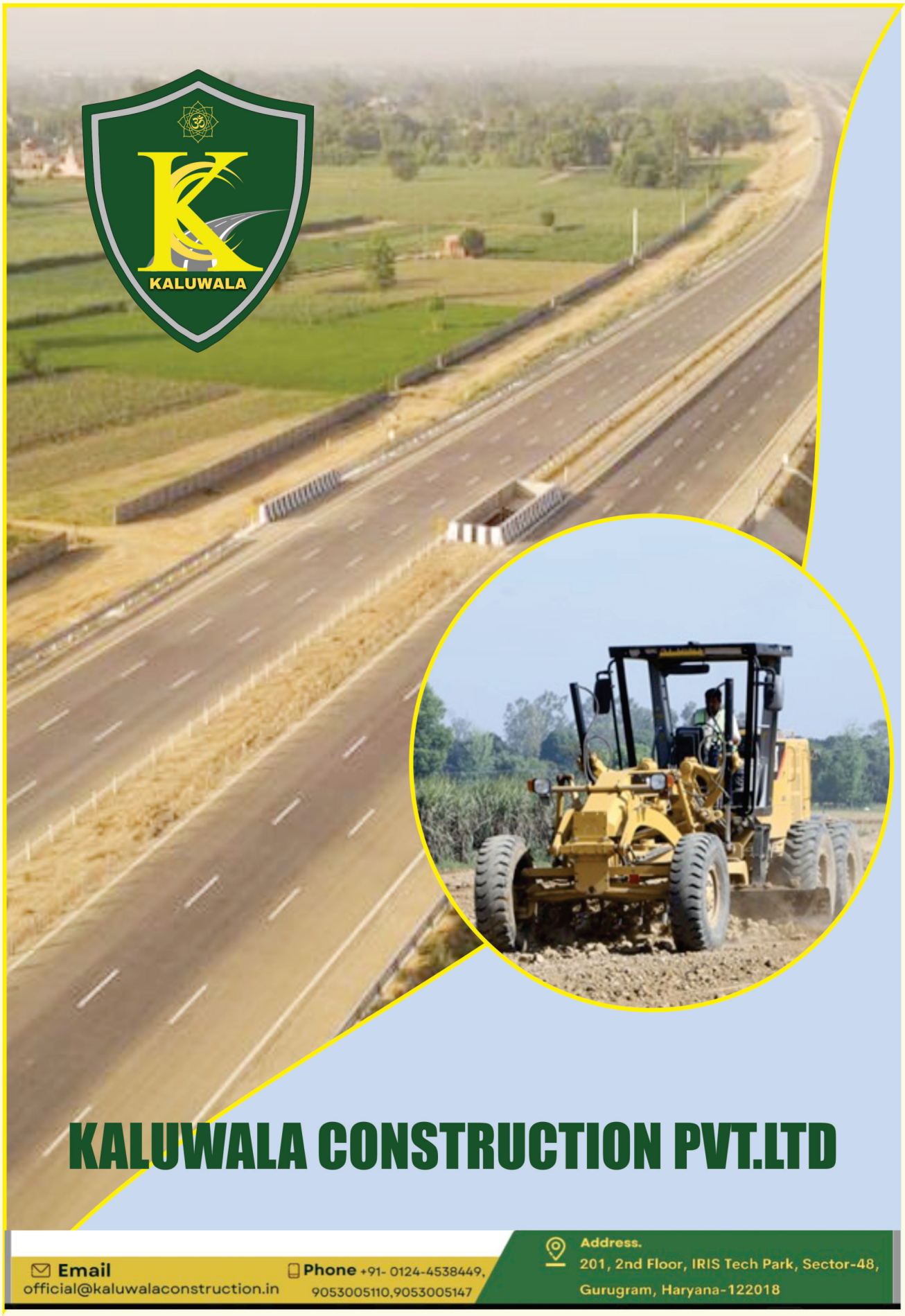

KALUWALA CONSTRUCTION PVT.LTD

Email
official@kaluwalaconstruction.in

Phone +91- 0124-4538449,
9053005110,9053005147

Address.
201, 2nd Floor, IRIS Tech Park, Sector-48,
Gurugram, Haryana-122018

Total Pages 52 with cover June, 2025 RNI No. DELHIN/2011/41355

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Navratna Enterprise) & JKSPDC Ltd. (A Govt. of J&K Enterprise)

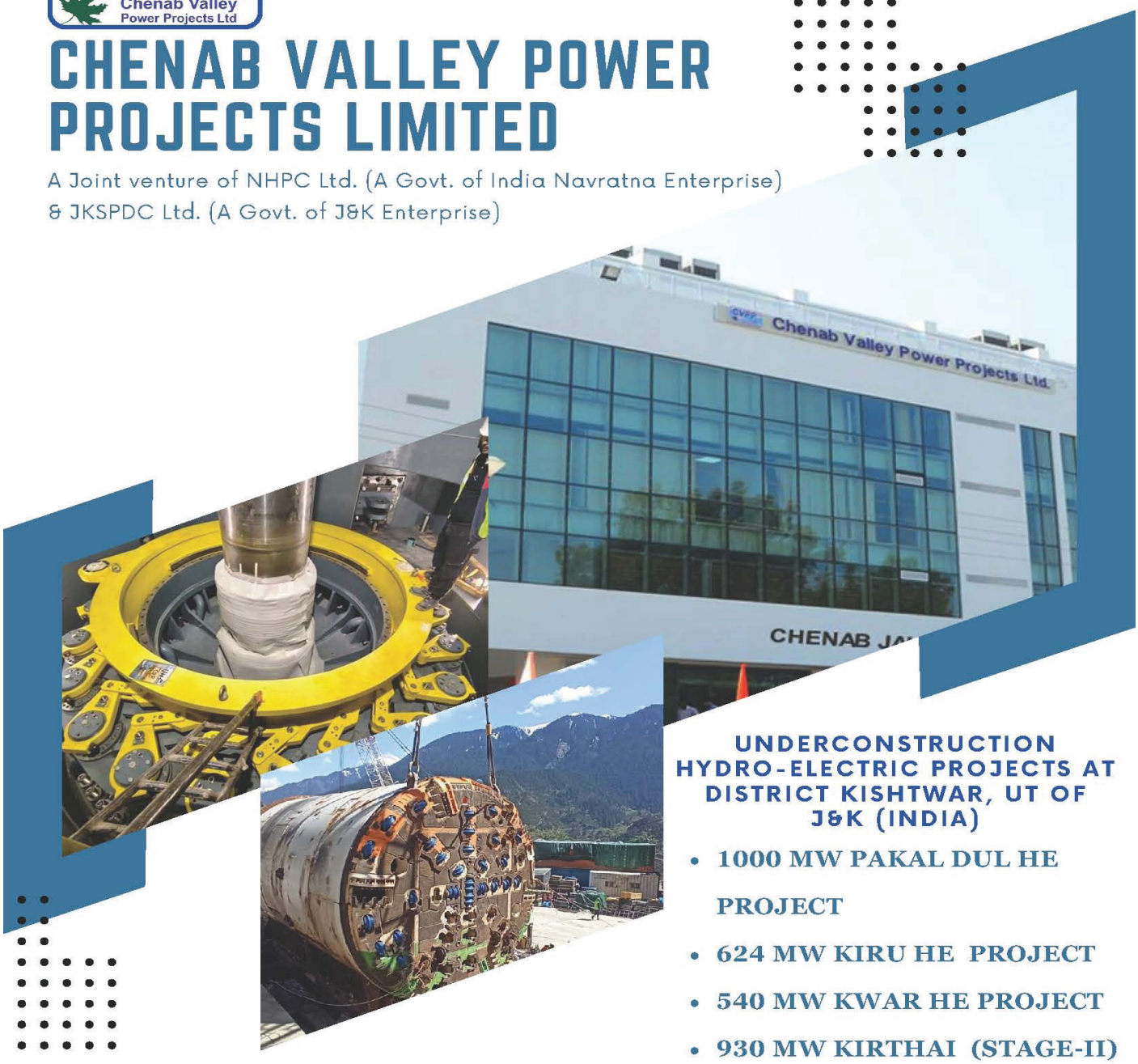

UNDERCONSTRUCTION HYDRO-ELECTRIC PROJECTS AT DISTRICT KISHTWAR, UT OF J&K (INDIA)

- 1000 MW PAKAL DUL HE PROJECT
- 624 MW KIRU HE PROJECT
- 540 MW KWAR HE PROJECT
- 930 MW KIRTHAI (STAGE-II) HE PROJECT

Building Nation Through Green and Clean Energy

Call for details
+91-191-2475516
WWW.CVPPINDIA.COM

Registered Office:
Chenab Jal Shakti Bhavan, Opposite Saraswati Dham,
Rail Head Complex, Jammu – 180012 (J&K)

@Cvpppl
@CvppplLimited
@CvppplLimited